सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 109, नई दिल्ली, बुधवार, 15 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 देश को जल्द मिलेगा नया PMO, केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी
05 EV सेगमेंट में छाएगा रॉयल एनफील्ड का जादू, 2024 में होगी नई बाइक की एंट्री
08 महिलाओं को एसयूवी ने मारी टक्कर, पांच की मौत

आज का सुविचार

हर दिन अच्छा हो ये जरुरी नही होता. पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरुर होता है.

दिल्ली-एनसीआर में सेकेंड हैंड कार बेचना होगा आसान, जल्द आ सकता है नया नियम

परिवहन विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले अगर कोई कंपनी लोगों से वाहन खरीदती थी तो परिवहन विभाग में आरसी स्थानांतरण होने तक संबंधित वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होती थी....

संजय बाटला

परिवहन विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले अगर कोई कंपनी लोगों से वाहन खरीदती थी तो परिवहन विभाग में आरसी स्थानांतरण होने तक संबंधित वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होती थी लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों को वाहनों के बेचने में आसानी होगी।

नोएडा। सेकेंड हैंड वाहन बेचना लोगों के लिए अब और आसान होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर पर कुछ महीनों में ही काम शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों व कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों को लाभ मिलेगा।

अभी तक बाजार में वाहन खरीदने वाली कंपनियां लोगों से लेनदेन तय होने के बाद एक निश्चित अवधि में वाहनों को बेचने का आश्वासन देती थीं। निश्चित अवधि में वाहनों की बिक्री संबंधित कंपनी से नहीं हो पाने पर लोगों को सुरक्षा संबंधी कई तरह की परेशानी सताने लगती थी।

ऐसे में लोग परिवहन विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। सरकार की तरफ से वाहन खरीदने वाली कंपनियों को अब मीडिएटर के रूप में अधिकृत करने पर काम किया जाएगा, जिसके पास वाहन विक्रेताओं से खरीदे वाहन को बेचने का अधिकार होगा। एक बार सौदा तय होने के बाद वाहन खरीदने वाली कंपनी की ही वाहन संबंधित पूरी जिम्मेदारी होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मिडिएटर की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी व वाहन मालिक वाहन खरीद बिक्री के अलावा अन्य प्रकार से भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसमें वाहनों के रंग रोगन उसकी कमियां दूर करने व वाहन की फिटनेस कराने, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ले जाने पर भी संबंधित कंपनी या लोग की ही वाहन

की पूरी जिम्मेदारी होगी।

परिवहन विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले अगर कोई कंपनी लोगों से वाहन खरीदती थी तो परिवहन विभाग में आरसी स्थानांतरण होने तक संबंधित वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होती थी, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों को वाहनों के बेचने में आसानी होगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डा. सियाराम वर्मा बताते हैं कि सुविधा शुरू होने पर पावर आफ अटार्नी का विकल्प मीडीएटरी कंपनी या व्यक्ति को रहेगी। इसके लिए आनलाइन प्रमाण पत्र भी जारी होगा।

दिल्ली-NCR में निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों का है बड़ा बाजार

दिल्ली- एनसीआर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियम के मुताबिक पेट्रोल वाहन 15 वर्ष व डीजल वाहन 10 वर्ष की उम्र तक ही चल सकते हैं। निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों के दिल्ली- एनसीआर में चलने पर पाबंदी है। सिर्फ दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह तक निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों की उम्र 54 लाख, गौतमबुद्धनगर में 121,230,गाजियाबाद, 2,83, 856 व हापुड़ में 25, 612 है।

आगामी दो महीने में यूपी के जिलों में शुरू हो सकती है सुविधा

गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण वीर बताते हैं कि 22 दिसंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित सकुर्लर जारी किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आने के बाद इसके शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक करीब दो महीने में प्रदेश सरकार की तरफ से इसपर काम शुरू करा दिया जाएगा।

चार जिलों में एक महीने में बिकते हैं 3 हजार सेकेंड हैंड वाहन

गाजियाबाद संभाग में गौतमबुद्दनगर, हापुड़, बुलंदशहर व गाजियाबाद जिला आते हैं। चारों जिलों में औसतन तीन हजार सेकेंड हैंड वाहन एक महीने में खरीदे व बेचे जाते हैं। यह सुविधा शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा।

इनसाइड

तीन महीनों में अपग्रेड करने होंगे जिलों में फिटनेस सेंटर

प्रदेश में चल रहे निजी फिटनेस सेंटर्स को अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के रूप में स्थापित करना होगा। वाहनों की जांच के लिए चल रहे फिटनेस सेंटर्स को अपग्रेड करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इसके बाद भी अगर फिटनेस सेंटर अपग्रेड नहीं हुए तो वाहनों की फिटनेस जांच के लिए अनफिट घोषित कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया है। आदेश में फिटनेस सेंटर्स को एक अप्रैल 2023 तक अपग्रेड करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इन तीन महीनों में प्रदेश के सभी निजी फिटनेस सेंटर्स को नए नियमों के अनुसार बदलाव करना होगा। सेंटर का साइज बढ़ाने के साथ नई मशीन लगानी होगी। इस काम पर खर्च होने वाली राशि निजी फिटनेस सेंटर्स को वहन करनी होगी। सरकार के इस निर्णय को लेकर फिटनेस सेंटर्स के मालिक दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। दरअसल, वर्तमान में जो निजी फिटनेस सेंटर चल रहे हैं, उनमें मशीनों के साथ मैन्यूअली भी काम होता है। एटीएस में वाहनों की जांच पूरी तरह से मशीनों के जरिए होगी।

पेट्रोल-डीजल कारों पर हट गया बैन? वायरल हो रहे इस मैसेज पर सरकार ने दिया ये जवाब

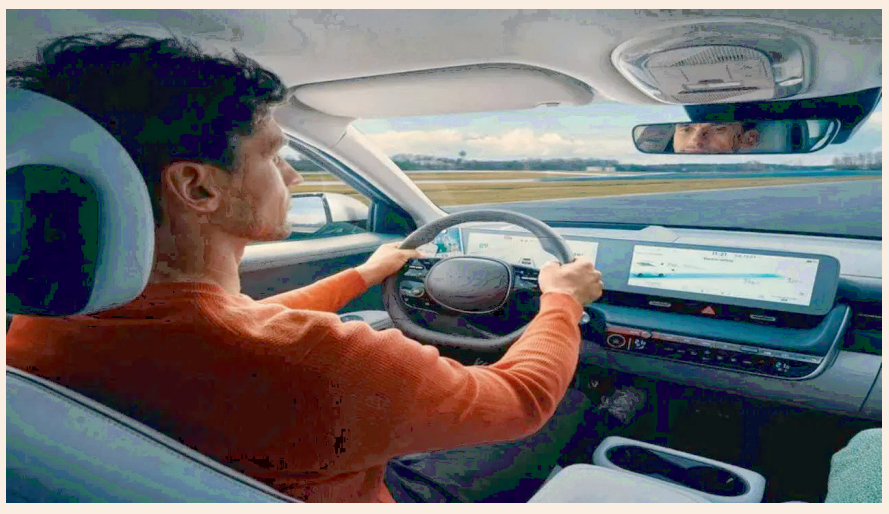

एनटीवी संवाददाता

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि NGT द्वारा पुराने वाहनों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया गया है. क्या है इस पोस्ट की सच्चाई, आइए जानते हैं कि सरकार का इस मामले में क्या कहना है.

नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन पर एनजीटी ने बैन लगाया था लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली और एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगाए इस प्रतिबंध को हटा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MoRTH ने नोटिफिकेशन जारी कर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पर लगे बैन को हटा दिया है.

वायरल हो रहे पोस्ट पर आया सरकार का जवाब

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट पर अब सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऑनलाइन इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन बता दें कि इस तरह के सभी दावे फर्जी है.

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि MoRTH इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में कोई भी सच्चाई नहीं है और सरकार ने इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है.

याद दिला दें कि नवंबर 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पुराने वाहनों पर बैन का ऑर्डर पास किया था. इस ऑर्डर को पास करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल और इससे पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने से रोका जाए जिससे कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की आबोहवा को स्वच्छ बनाया जा सके और प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके.

भोपाल: कृपया ध्यान दें! अब एमपी में डीएल बनवाना होगा महंगा

भोपाल। मध्य प्रदेश सहित भोपाल के लोगों के लिए ये खबर जानना जरूरी है। बता दें कि, आने वाले समय में एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना टिपिकल होने सहित महंगा भी हो सकता है। इसे लेकर सूबे के परिवहन मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर इंदौर व छिंदवाड़ा में प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च खोलने की मंजूरी मिल गई है। महकमे के आला अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। इधर, अगर से सब कुछ समय पर हुआ तो अब एमपी के इन बड़े शहरों में डीएल बनवाना महंगा होगा। वहीं डीएल बनवाना अब और कठिन हो जाएगा। परिवहन आयुक्त संजय कुमार के मुताबिक प्रदेश में शुरुआती दौर में जिला स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगरौली में आर्यन मोटर, सतना में सार्थक वेल फेयर सोसायटी व धार में मालवा ड्राइविंग में खोलने की योजना को मंजूरी दी गई है। परिवहन आयुक्त के मुताबिक, वर्तमान में अभी 75 आवेदन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में लंबित चल रहे हैं, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, राज्य में अब हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब ड्राइवर इन्हें पहले चलाने का प्रशिक्षण लेंगे। 6 सप्ताह तक की ट्रेनिंग लेने की एवज में चालक को 10 हजार रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर व छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोलने को मंजूरी दी है।

सड़क सुरक्षा मानकों पर विशेषज्ञों से परामर्श शुरू

एनटीवी संवाददाता

मानक प्राधिकरण के तहत एक उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्गों और जिले की अन्य सड़कों के लिए सुरक्षा मानक तय करेगी, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे

सरकार राजमार्गों के लिए सड़क सुरक्षा सूचकांक पेश कर सकती है। इसके लिए सड़क और राजमार्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत शुरू हो गई है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि एकसमान सड़क सुरक्षा मानक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ मिलकर विभिन्न हिस्सेदारों के साथ बैठक की, जिसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है।

बैठक के दौरान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बीआईएस, आईआईटी दिल्ली और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मानक प्राधिकरण के तहत एक उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्गों और जिले की अन्य सड़कों के लिए सुरक्षा मानक तय करेगी, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आकलन और गुणवत्ता जांच में बीआईएस सड़क सुरक्षा संगठनों की भी मदद करेगी।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'सड़क सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य ध्यान 4 E पर है। इसमें इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल शामिल है।' वाहनों की संख्या बढ़ने और सड़क नेटवर्क के तेजी से विस्तार के कारण भारत में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें जन जागरूकता, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल शामिल है। हाल ही में सरकार ने अगले 3 माह में सभी राजमार्गों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट के दिशानिर्देश दिए थे। इसमें निर्माणाधीन राजमार्ग और और यहां तक

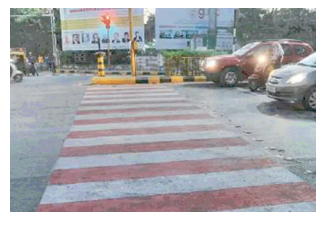

कि डिजाइनिंग के स्तर पर राजमार्गों के काम शामिल हैं।

इंजीनियरिंग के पहलुओं के लिए इंडियन रोड कांग्रेस संहिता के अलावा भारत में सड़क सुरक्षा के लिए प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल को लेकर कुल मिलाकर एकसमान मानक नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, 'इस समय अधिकारी सिर्फ इंजीनियरिंग के पहलुओं की जांच करते हैं, लेकिन हम कुल मिलाकर सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी नियम परिभाषित करने वाले मानक लाने जा रहे हैं।'

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक यात्रा के दौरान दुर्घटना के मामले 2020 में 3,68,828 थी, जो 2021 में बढ़कर 4,22,658 हो गई। इनमें 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं, 17,993 रेल दुर्घटनाएं और 1,550 रेलवे फाटक पर होने वाली दुर्घटनाएं थीं। एनसीआरबी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या 2020 में 1,33,201 थी, जो 16.8 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 1,55,622 हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय रही है।

दिल्ली में अलग-अलग मार्गों पर रोजाना हजारों बसों में लाखों यात्री सफर करते हैं।

रोहिणी के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में 1 मार्च से गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज

एसडी सेठी

नई दिल्ली, एनटीवी। दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लोगों को 1 मार्च से मुफ्त इलाज मिलेगा।इस बावत मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष अस्पताल के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि 1 मार्च से बाह्य रोगी विभाग ओपीडी में 25 फीसदी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) में 10%फीसदी तक गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया होगा।

वहीं आईपीडी में (ईडब्ल्यूएस) मरीजों के लिए 31 बिस्तर उपलब्ध होंगे। पीठ ने कहा कि अस्पताल को अपने ब्यान पर कायम रहते हुए गरीबों को निशुल्क इलाज देना होगा। गैर सरकारी संस्था सोशल

जूरिस्ट ने साल 2018 में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया था कि अस्पताल को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आवंटन में शर्त थी कि अस्पताल गरीब रोगियों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराना होगा। लेकिन अस्पताल डीडीए के कांट्रैक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं कर रहा था। इस बावत साल 2007 में हाई कोर्ट व जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पतालों को इसी अनुपात मे निशुल्क इलाज करने के आदेश दिए थे। लेकिन राजीव गांधी कैंसर अस्पताल ने पिछले दो दशको में किसी भी गरीब मरीज का मुफ्त इलाज नहीं किया।

और अनुचित मुनाफा कमाया है। एनजीओ ने मांग की थी कि भूमि आवंटन की शर्तों के मुताबिक अस्पताल में गरीब मरीजों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। अस्पताल द्वारा कमाये गये आवंटत मुनाफे की वसूली की प्रकिया शुरू करने संबंधी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

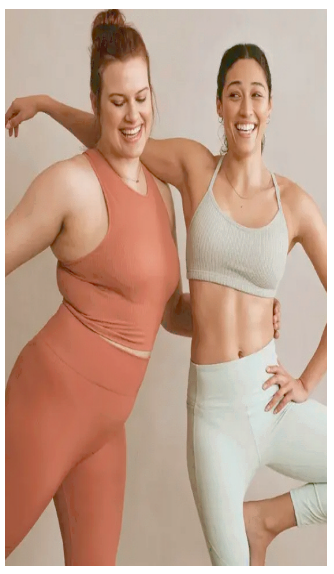

अपनाएं ये बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स, खुद से हो जाएगा प्यार

18-30 की उम्र के बीच की 70% महिलाएं अपने शरीर को नापसंद करती हैं और 45% पुरुष भी अपने शरीर से असंतुष्ट हैं. ऐसे में बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है.

शारीरिक बनावट के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचने में अधिक समय बिताएं.

क्या आपने हाल ही में रिलीज़ हुआ 'डबल एक्सेल' का ट्रेलर देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड मूवी डबल XL का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसमें सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब देती नजर आ रही हैं. इसके ट्रेलर में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी दिखाई दे रहे हैं. फिल्म में एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जिससे कई लोग वाबस्ता हैं. हालांकि, आज के दौर में बहुत लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाया है लेकिन आज भी कई लोग, खासकर महिलाएं अपनी बनावट और बॉडी के कारण परेशान रहती हैं. किसी को दुबला तो किसी को मोटा कह कर चिढ़ाया जाता है, जो कि गलत है. जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हेल्दी बॉडी होने का मतलब भी एक जैसा हो.

रोग मुक्त होने के लिए एक ही तरह की बॉडी आइडियल नहीं होती. हो सकता है एक इंसान की नजर में जो शख्स अस्वस्थ हो, वो असल में हेल्दी ही हो. सबका आकार अलग है और इसमें कुछ गलत नहीं है. आपको बता दें कि वेलबींगट्रस्ट डॉट ओआरजी के अनुसार 18-30 की उम्र के बीच की 70% महिलाएं अपने शरीर को नापसंद करती हैं और 45% पुरुष भी अपने शरीर से असंतुष्ट हैं. अगर आप भी अपने शरीर को लेकर सहज महसूस नहीं करती हैं तो आज हम आपको कुछ बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने शरीर को आपका हर रोज साथ देने के लिए धन्यवाद कहने लगेंगी, जो कि जरूरी भी है.

अपनाएं ये बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स

पॉजिटिव अफर्मेशन्स बोलें

बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है. इसका अभ्यास करने के सबसे बुनियादी और प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन्स को ज़ोर से बोलें, खासकर जब हम अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस न कर पा रही हों. खुद से कहें- 'मैं काफी हूं', 'मैं सुंदर हूं', 'मैं किसी से कम नहीं हूं', 'मैं हर हाल में और हर तरह से खूबसूरत हूं'.

उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको अपने बारे में हैं पसंद

हर बार जब आपके दिमाग में आपके शरीर के बारे में कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसका मुकाबला कुछ सकारात्मक सोचकर करें. उन चीजों की लिस्ट बनाने की कोशिश करें जो आपको अपने शरीर के बारे में पसंद हैं.

दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें

लोगों की शेप अलग-अलग होती है. एक इंसान एक तरह से खूबसूरत होता है तो दूसरा इंसान किसी और तरह से अच्छा लग सकता है. दूसरों से अपनी तुलना करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप वैसे नहीं दिखते जैसे आपको दिखना चाहिए लेकिन आपको किसी और की तरह नहीं दिखना है क्योंकि सब एक जैसे दिखाई देंगे तो यह बहुत बोरिंग लग सकता है.

नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें

अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी मित्र के साथ करते हैं. अगर आप अपने शरीर के बारे में जो कुछ भी कहते हैं वैसा कुछ आप अपने किसी दोस्त के बारे में या उसके शरीर के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत होगा तो ऐसा अपने साथ भी मत कीजिए. नेगेटिव सेल्फ टॉक ही हमें शरीर के लिए नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है.

60 की उम्र के बाद महिलाएं ऐसे रखें सेहत का ख्याल, फॉलो करें 5 हेल्थ टिप्स

60 प्लस के बाद ज्यादातर महिलाएं सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का शिकार हो जाती हैं. कुछ महिलाओं को भूलने की बीमारी होने लगती है. ऐसे में ब्रेन एक्सरसाइज करने से लेकर डेली वर्कआउट, कुछ हेल्थ चेकअप करवाकर आप बढ़ती उम्र में भी खुद को फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं.

साठ साल की उम्र के बाद ज्यादातर महिलाओं को सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सेहत सही रखने के लिए महिलाएं अक्सर दवाइयों पर निर्भर हो जाती हैं. अगर आपकी उम्र भी 60 साल से अधिक है तो कुछ आसान टिप्स फॉलो (Health care tips) करके आप ना सिर्फ सेहत का खास ख्याल रख सकती हैं, बल्कि अपनी हेल्थ और मूड दोनों को बेस्ट बना सकती हैं.

बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं का शरीर कमजोर होने लगता है, जिसके चलते वे कुछ बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं. इसके अलावा, ज्यादातर महिलाओं को अल्जाइमर या भूलने की बीमारी भी होने लगती है. वेबएमडी डॉट कॉम पर बताए गए कुछ आसान हेल्थ टिप्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो करके 60 के बाद भी खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं.

ब्रेन एक्सरसाइज करें

60 साल के बाद भी माइंड को शार्प और एक्टिव रखने के लिए आप ब्रेन एक्सरसाइज कर सकती हैं. ऐसे में अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करें. इसके लिए आप पजल सॉल्व करने, नई हॉबी ट्राई करने, नई भाषा सीखने और एडवेंचर करने जैसे कुछ तरीकों की मदद ले सकती हैं.

वर्कआउट करें

साठ साल के बाद शरीर की मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते महिलाएं कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और अन्य ज्वॉइंट पेन का शिकार हो सकती हैं. ऐसे में मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आप हर रोज फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट ट्राई कर सकती हैं. इससे आप 60 के बाद भी फिट और हेल्दी रहेंगी.

स्मोकिंग से दूर रहें

कुछ महिलाओं को स्मोकिंग या तम्बाकू खाने की आदत होती है मगर 60 वर्ष की उम्र के बाद स्मोकिंग करने से दिल की बीमारी या कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में 60 के बाद भी सेहतमंद रहने के लिए स्मोकिंग या धूम्रपान की लत छोड़ना बेहतर रहता है.

स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं

65 साल तक महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है. ऐसे में ना सिर्फ महिलाओं की हड्डियां कमजोर होने का डर रहता है बल्कि आपको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है. इसलिए 60 साल के बाद महिलाओं के लिए रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग करवाना जरुरी हो जाता है.

वैक्सीन लेना ना भूलें

साठ साल के बाद शरीर की इम्यूनिटी वीक होने लगती है. ऐसे में डॉक्टर की सलाह से जरूरी वैक्सीन लगवाकर आप बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकती हैं. साथ ही वैक्सीन की मदद से आप कई गंभीर बीमारियों को भी आसानी से मात दे सकती हैं.

कम उम्र में महिलाएं हो रही हैं हार्ट अटैक का शिकार

आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं ज्यादातर सामने आ रही हैं जिनमें खराब लाइफस्टाइल की आदतें और बढ़ता मोटापा या अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कारण शामिल हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना एक आम समस्या बन गई है. यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो अक्सर लोगों की जान ले सकती है. हार्ट अटैक के सबसे सामान्य लक्षण सीने में दर्द या दबाव महसूस होना होते हैं. यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है. एक्सपर्ट्स की माने तो यह समस्या कम उम्र के लोगों और खासकर महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिल रही है. यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि वृद्धो में दिल के दौरे के दर में कमी आयी है और यही संख्या युवाओ में बढ़ी है. इसमें भी खासकर महिलाओं को हार्ट अटैक ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज और मोटापा आदि हो सकते है. आइए जानते हैं

महिलाओं में हार्टअटैक की समस्या होने के कारण

हाई ब्लड प्रेशर

हॉपकिंस मेडिसिन डॉट ओआरजी के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल सकती है. हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं. लाइफस्टाइल की कुछ गलत आदतों के कारण या महिलाओं में गर्भावस्था और बर्थ कंट्रोल पिल्स हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क को बढ़ा देती है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के साथ-साथ स्मोक भी करती हैं तो इससे ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना अधिक हो जाती है.

हाई कोलेस्ट्रॉल

एस्ट्रोजन महिलाओं को एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाने का काम करता है लेकिन मेनोपॉज़ जैसी स्थिति के बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना अधिक हो जाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है.

स्मोकिंग

स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. ऐसे में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में स्मोकिंग करने वाले पुरुषों की तुलना में हार्ट डिजीज विकसित होने का खतरा और ज्यादा अधिक होता है.

निकोटीन आपकी बॉडी के सभी भागों जैसे हार्ट और ब्लड वेसल्स से लेकर आपके हार्मोंस, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन तक, को प्रभावित कर सकता है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के अन्य कारणों में डायबिटीज, मोटापा, जेनेटिक्स हार्ट समस्याएं, उम्र, अत्यधिक शराब का सेवन और खराब लाइफस्टाइल शामिल हो सकते हैं.

महिलाओं के लिए नौकरी की तुलना में सेल्फ एम्प्लॉई होना ज्यादा फायदेमंद! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

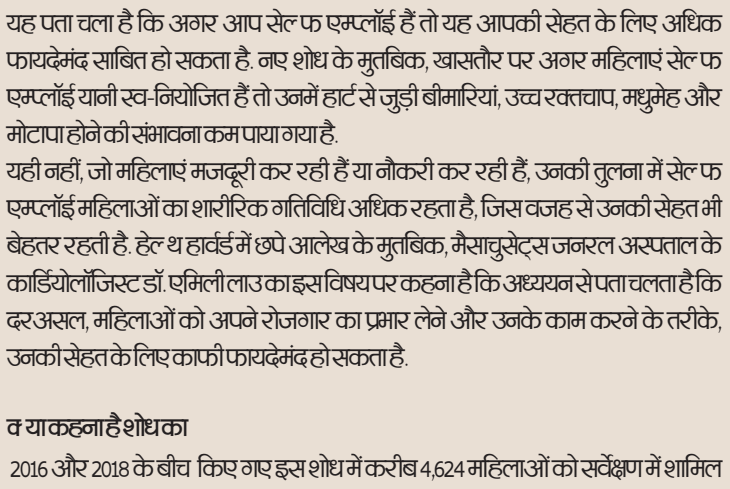

शोधों में पाया गया कि जो महिलाएं सैलरी लेती हैं या किसी और के लिए काम करती हैं, उनमें हृदय रोग, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलीं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉई महिलाएं अधिक फिट और हेल्दी पाई गईं.

आमतौर पर यह माना जाता है कि नौकरी करना बिजनेस करने की तुलना में कम स्ट्रेसफुल होता है. यही वजह है कि महिलाएं नौकरी करना अधिक सेफ समझती हैं, लेकिन नए शोध में यह पता चला है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है. नए शोध के मुताबिक, खासतौर पर अगर महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉई यानी स्व-नियोजित हैं तो उनमें हार्ट से जुड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा होने की संभावना कम पाया गया है.

यही नहीं, जो महिलाएं मजदूरी कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं, उनकी तुलना में सेल्फ एम्प्लॉई महिलाओं का शारीरिक गतिविधि अधिक रहता है, जिस वजह से उनकी सेहत भी बेहतर रहती है. हेल्थ हार्वर्ड में छपे आलेख के मुताबिक, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ का इस विषय पर कहना है कि अध्ययन से पता चलता है कि दरअसल, महिलाओं को अपने रोजगार का प्रभार लेने और उनके काम करने के तरीके, उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

क्या कहना है शोध का

2016 और 2018 के बीच किए गए इस शोध में करीब 4,624 महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया और इनके आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया जिसमें वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित या मजदूरी के लिए काम करने वाली थीं. ये सभी 50 वर्ष से अधिक आयु की थीं और लगभग 16% प्रतिभागी सेल्फ एम्प्लॉई थीं जबकि बाकी सैलरी पानी वाली थीं. इनमें पाया गया कि जो महिलाएं सैलरी लेती हैं या किसी और के लिए काम करती हैं, उनमें हृदय रोग, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली.

क्या पाया गया शोध में

अध्ययन में पाया गया कि स्वरोजगार करने वाली महिलाओं में मोटापे की संभावना 34% कम पाई गई, उच्च रक्तचाप की संभावना 43% कम थी और वेतन या मजदूरी के लिए काम करने वालों की तुलना में मधुमेह की संभावना 30% कम दिखी. इस बीच, स्व-नियोजित महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कम था और वे अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय थीं. जबकि 80% महिलाओं ने कहा कि वे अन्य प्रतिभागियों के 72% की तुलना में सप्ताह में कम से कम दो बार व्यायाम करती हैं. ये सारी चीजें हार्ट के हेल्थ को काफी हद तक प्रभावित करते हैं.

बनना चाहती हैं इंडिपेंडेंट? होम मेकर्स कम पैसों में शुरू कर सकती हैं ये 5 तरह के बिजनेस

कोई भी काम शुरू करने से पहले इन्वेस्टमेंट का सोचकर हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं लेकिन ऐसे कई बिजनेस हैं जिन्हें एकदम कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर खूब पैसा कमाया जा सकता हैं.

आजकल समय बदल रहा है, जिसके चलते हर कोई एक अच्छे रोजगार और इनकम की तलाश में रहता है. बढ़ती महंगाई ने सबकी आंखें खोल दी हैं, अधिकतर लोग अब मानते हैं कि आजकल काम छोटा हो लेकिन अपना होना चाहिए. आज के समय में पुरुषों और महिलाओं, दोनों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उन्हें किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े.

ऐसे में महिलाएं घर को संभालने के साथ-साथ पैसे तो कमाना चाहती हैं लेकिन वे अक्सर बिजनेस की फंडिंग और आगे का सोचकर कदम नहीं बढ़ा पाती हैं, अगर आपके साथ भी ऐसे ही स्थिति है तो हम आपके लिए बहुत अच्छे और शानदार बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएं हैं जिससे कम इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है.

आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई, ऑफिस या किसी काम के चलते घर से बाहर रहते हैं, जिसके चलते वे घर के बने फ्रेश खाने की तलाश में रहते हैं. आप अपनी किचन से टिफिन सर्विस शुरू कर सकती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम और फायदा ज्यादा होता है. बिजनेस में ज्यादा मुनाफे के लिए क्वालिटी का ख्याल रखें.

मेकअप आर्टिस्ट

अगर आप मेकअप या फेशियल करना जानती हैं तो आप अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकती हैं. आजकल ऐसी सर्विसेज काफी ट्रेंड में हैं और ये एकदम लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है. आप अपने मेकअप ट्यूटोरियल के विडियोज बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं.

सिलाई का बिजनेस

आजकल हर रोज बदलते फैशन के दौर में नए-नए डिजाइनर कपड़ों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है इसी मौके का फायदा उठाकर आप कपड़ों की सिलाई का काम घर बैठे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकती हैं और घर पर ही टेलरिंग शॉप शुरू कर सकती हैं.

हैंडक्राफ्ट सेलर

आजकल सभी अपने घरों को सजाने के लिए आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में इनकी मांग बढ़ती जा रही है, इस मांग को देखते हुए आप जिस प्रकार अपने घर को सजाती हैं ठीक उसी तरह छोटे-छोटे हैंडक्राफ्ट्स बनाकर बेच सकती हैं.

सेल्स बिजनेस

आजकल सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आप सोशल मीडिया के जरिए भी कम इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं. आप ऑनलाइन ज्वेलरी, कपड़े, गिफ्ट्स या दूसरी चीजें

इनसाइड

फिल्मों में काम दिलाने के बहाने करता था ठगी, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक

दिल्ली पुलिस ने खुद को निर्देशक-निर्माता के रूप में प्रस्तुत करने और कई युवाओं को अभिनय की दुनिया में काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को युवाओं को फिल्म का काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिल्मी दुनिया में काम दिलाने का झांसा कर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपये ऐठ चुका है। ओझा के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी की बारे में जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को निर्देशक-निर्माता के रूप में प्रस्तुत करने और सैकड़ों युवाओं को अभिनय के अवसर दिलाने के नाम पर ठगने वाले 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के अनुज कुमार ओझा के रूप में हुई है, जिसने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी को आव्या के नाम से रजिट्रेशन कर रखा था। वह अक्सर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वेब सीरीज, धारावाहिकों और विज्ञापनों में एक्टिंग के कई ऑडिशनों के बारे में जानकारी साझा लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला, वह पंचकुला में एक मामले में भी वांछित था, जिसमें ₹छोटी सरदारनी₹ नामक धारावाहिक में एक महिला को भूमिका निभाने का आश्वासन देकर उसे धोखा दिया गया था। दिल्ली पुलिस को निर्देशक-निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर ठगी करने वाले की जानकारी अक्टूबर, 2022 में नरेला के एक निवासी ने शिकायत द्वारा दी थी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने कहा- उसने एक पेड ब्रांड शूट के बारे में ओझा की इंस्टाग्राम स्टोरी देखने के बाद आरोपी से संपर्क किया था, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे शूटिंग के लिए एक समझौते पर साइन करए और भुगतान के रूप में 75,000 रुपये भी मांगे। पैसों के भुगतान करने के बाद, ओझा ने कहा कि उनकी अग्रिम राशि दो दिनों में उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन बाद में प्रोफाइल अपडेट और आयकर संबंधी मामले का बहाना लगाकर लगाभग साढ़े चार लाख रुपये(4, 43, 142) की ठगी की।

दुबई भाग गया था आरोपी: पुलिस

पुलिस ने कहा कि पीड़ित को धोखा देने के बाद, ओझा कथित तौर पर दुबई गया। वहीं, मामले की जांच के लिए इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी गईं थीं, जिसके माध्यम से आरोपी कथित रूप से युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता था। उनकी कॉल डिटेल और मनी ट्रेल का विश्लेषण किया गया।

इंदौर से आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) रवि कुमार सिंह ने कहा कि ओझा का पीछा किया गया, लेकिन वह अपना ठिकाना बदलता रहा, लेकिन 6 फरवरी को हमारी टीम को सूचना मिली कि ओझा तुलसी एक्सप्रेस में सवार होकर भोपाल जाएंगे। इसके बाद एक टीम भोपाल भेजी गई, जहां से इंदौर भागने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ लिया गया। उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।₹ पुलिस ने कहा कि पढ़ाई के बाद मुंबई जाने के बाद ओझा अपने पड़ोसी राकेश सिंह के संपर्क में आया और उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन कंपनी का पंजीकरण कराया। उन्होंने तीन गानों के वीडियो शूट किए और उन्हें YouTube पर रिलीज़ किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इवेंट और विज्ञापन प्रचार का आयोजन भी शुरू किया। जब लोगों ने उससे संपर्क करना शुरू किया, तो उसने अभिनय में अवसर प्रदान करने के नाम पर उन्हें ठगना शुरू कर दिया।

देश को जल्द मिलेगा नया PMO, केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी, केंद्र से रखी थी यह शर्त

निर्माण कर रही एजेंसी को प्रत्यारोपित किए जा रहे पेड़ों के बदले 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे।

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में समय से कार्रवाई की जिसकी वजह से परियोजना को गति देने में मदद मिली है।

नईदिल्ली। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के अधीन बन रहे प्रधानमंत्री के नए आवास का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मामले में हरी झंडी मिलने के बाद अब राष्ट्र को नया प्रधानमंत्री आवास जल्द मिलने की राह आसान हो गई है। यह एक्जीक्यूटिव एंक्लेव दिल्ली के अतिसुरक्षित लुटियन्स जोन में आने वाले साउथ ब्लॉक के दक्षिण दिशा में प्लॉट नंबर 36/38 पर बन रहा है।

गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा समेत प्राइम मिनिस्टर्स एंक्लेव का निर्माण कर रही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार से इसके लिए 173 पड़ों को निर्माणाधीन साइट से प्रत्यारोपित करने की अनुमति मांगी थी।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में समय से कार्रवाई की जिसकी वजह से परियोजना को गति देने में मदद मिली है। केजरीवाल सरकार ने इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि निर्माण कर रही एजेंसी को प्रत्यारोपित किए जा रहे पेड़ों के बदले 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे।

प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इस एक्जीक्यूटिव एंक्लेव का हिस्सा होंगे जिनके निर्माण का अनुमानित खर्च 1,189 करोड़ रुपये है।

इंडिया हाउस में कॉन्फ्रेंस की सुविधा होगी जैसे अभी हैदराबाद हाउस में है। जिस तरह से अभी हैदराबाद हाउस में विदेशों से आने वाले उच्चस्तरीय नेताओं की देश के नेताओं के साथ बैठक होती है वैसी ही सुविधा इंडिया हाउस में होगी।

सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास, देश का पावर कॉरिडोर, एक नई संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय व निवास और एक नए उपराष्ट्रपति एंक्लेव की परिकल्पना करता है।

न्यूनतम वेतन से कम पर विज्ञापित जॉब पोस्टिंग पर HC ने सरकार से मांगा जवाब, 23 फरवरी को होगी सुनवाई

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से कम पर जॉब पोस्टिंग की विज्ञप्ति पर दिल्ली सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। सरकार पर आरोप है कि वेबसाइट पर नौकरी की पोस्टिंग तय न्यूनतम वेतन से कम पर विज्ञापित की जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से कम पर जॉब पोस्टिंग की विज्ञप्ति पर दिल्ली सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसकी वेबसाइट पर नौकरी की पोस्टिंग तय न्यूनतम वेतन से कम पर विज्ञापित की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल के माध्यम से सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह किसी को दिल्ली सरकार के एनसीटी या किसी अन्य स्थान के आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से नीचे विज्ञापन रिक्तियों की अनुमति न दे।

23 फरवरी को मामले की होगी सुनवाई

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से इस मुद्दे पर अधिकारियों से निर्देश लेने को कहा और मामले को 23 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान अहमद ने दावा किया कि वह श्रमिकों या मजदूरों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, श्रम कानूनों को लागू करने और दिल्ली में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की मांग कर रहा था।

सरकार के वकील ने कोर्ट में दिया जवाब

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि निजी नौकरियों को COVID-19 महामारी के दौरान विज्ञापित किया गया था और वे सरकार से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सर्कुलर बहुत स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी का पालन करना होगा। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिस पर रोजगार के हजारों अवसरों का विज्ञापन किया जा रहा है।

सरकार के 2022 के आदेश का उल्लंघन

कहा गया कि ऑफिस बॉय, फील्ड मार्केटिंग कर्मचारी, कॉलिंग कर्मचारी, रसोइया, वेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिलेशनशिप मैनेजर, किचन हेल्पर, एम्बुलेंस ड्राइवर, चपरासी, सुरक्षा गार्ड और अकाउंटेंट सहित विभिन्न नौकरी के अवसरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से नीचे सरकार के 2022 के आदेश का उल्लंघन करके विज्ञापित किया जा रहा था।

याचिका में कहा गया है, ₹सरकारी पोर्टल से यह स्पष्ट है कि दिल्ली के एनसीटी में श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि नौकरी के अवसरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पर विज्ञापित किया जा रहा है।₹ याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने कर्मचारियों को वैध वेतन भुगतान के लिए अधिकारियों से संपर्क किया था लेकिन वे कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

CM केजरीवाल की रणनीति को काउंटर करेगी BJP नेताओं की मौजूदगी वाली अग्रकुल संस्था, वैश्य समाज होगा एकजुट

दिल्ली भाजपा के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल की अगुवाई में अग्रकुल संस्था ने दिल्ली में वैश्य समाज को लामबंद करने का संकल्प जताया है। शनिवार रात वेस्टर्न कोर्ट में हुई संस्था की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के साथ-साथ कई दिग्गज शामिल हुए।

नई दिल्ली। समाजसेवी और दिल्ली भाजपा के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल की अगुवाई में अग्रकुल संस्था ने दिल्ली में वैश्य समाज को लामबंद करने का संकल्प जताया है। शनिवार रात वेस्टर्न कोर्ट में हुई संस्था की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष और संस्था के संयोजक विष्णु मित्तल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भाजपा विजेंद्र गुप्ता सहित वैश्य समाज के गणमान्य लोग, व्यवसायी, शिक्षाविद आदि शामिल हुए।

बैठक में वैश्य समाज को एकजुट करते हुए राजनीतिक रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ाने के साथ वैश्य समाज की बेहतरी के लिए हर तरह से समर्पित होकर कार्य करने को कहा गया। गौरतलब है कि अग्रकुल की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के बाद संस्था की यह पहली बैठक थी। बैठक में बड़े भाजपा नेताओं की मौजूदगी से माना जा रहा है अग्रकुल संस्था के माध्यम से भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रणनीति को काउंटर करेगी।

पूरी दिल्ली में चलेगा मिशन

विष्णु मित्तल ने कहा कि अग्रकुल संस्था का मकसद वैश्य समाज की विरासत, संस्कृति और समाज का देश के प्रति योगदान को रेखांकित करना और एकजुट होकर अपनी समस्याओं पर मंथन करना था। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था लगातार पूरी दिल्ली में मिशन चलाकर वैश्य समाज के लोगों को लामबंद करने का काम करेगी।

हालांकि, संस्था के संयोजक विष्णु मित्तल ने इसे गैर राजनीतिक कवायद बताया। लेकिन माना जा रहा है वैश्य समाज को भाजपा से जोड़ने और बिखराव रोकने के लिए बैठकों का निरंतर सिलसिला शुरू किया का रहा है।

केजरीवाल को झटका देने की तैयारी

सूत्रों का कहना है कि भाजपा कई स्तरों पर दिल्ली में भाजपा को मजबूत कर केजरीवाल को झटका देने की तैयारी में है। पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में भी जुट गई है। दिल्ली में वैश्य समाज बड़ी संख्या में केजरीवाल से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिलता है लेकिन पार्टी चाहती है कि वैश्य समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ा रहे।

महरौली बुलडोजर एक्शन पर डीडीए को नोटिस हाईकोर्ट ने याचिका पर मांगा जवाब

दिल्ली के महरौली में डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका में क्षेत्र का नया सीमांकन नहीं होने तक अभियान को चलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के महरौली में डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका में क्षेत्र का नया सीमांकन नहीं होने तक अभियान को चलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

HC ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

सोमवार को भी डीडीए का डिमोलिशन ड्राइव लगातार चौथे दिन जारी रहा है। हालांकि सोमवार को हाईकोर्ट ने स्टे नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मंगलवार को एक बार फिर से महरौली में विध्वंसीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

महरौली बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को नोटिस जारी किया। अदालत ने महरौली माइनारिटी रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव का लोग विरोध कर रहे हैं।

AAP विधायक ने उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी

सोमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने ध्वस्तीकरण को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर महरौली विध्वंस अभियान रोकने और नए सिरे से सीमांकन के लिए दिल्ली सरकार के आदेश को लागू करने के लिए कहा है।

डीडीए के अभियान पर लोगों का विरोध

इससे पहले रविवार सुबह पहुंचे बुलडोजर ने आम बाग, बृजवासी कॉलोनी क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराया। डीडीए की तोड़फोड़ के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। डीडीए डिमोलिशन ड्राइव के दौरान पुलिस भी तैनात रहे।

शनिवार को अवैध कब्जे को हटाने के दौरान एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा, ₹राजस्व विभाग द्वारा अनाधिकृत और अवैध अतिक्रमण या निर्माण की सीमा की पहचान कर दिसंबर, 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आया हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने अलकायदा के 4 आतंकियों को सुनाई 7 साल की सजा, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने अलकायदा के चार आतंकियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा की अवधि पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई।

नई दिल्ली। देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने अलकायदा के चार आतंकियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान कासमी, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद और अब्दुल सामी को सात साल व पांच महीने कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सजा की अवधि पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोप लगाया था कि आतंकी कासमी ने उत्तर प्रदेश में एक मदरसा चलाया था, जहां कई छात्रों का दाखिला हुआ था और वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि मसूद युवाओं के बीच अल-कायदा के आतंकी एजेंडे का प्रचार कर रहा था और उन्हें आतंकी संगठन की ओर लुभाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आसिफ को दिल्ली के सीलमपुर से, जबकि कासमी को ओडिशा के कटक के जगतपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि कासिम के सऊदी अरब, पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय संबंध होने का संदेह भी था।

पड़ोसी ने कारोबारी से मांगी थी 30 लाख की रंगदारी, गिरफ्तार; बेटे की हत्या करने की दी थी धमकी

गाजियाबाद में एक कारोबारी से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने रंगदारी की रकम न देने पर कारोबारी के इकलौते बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी।

गाजियाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र के कड़कड़ माडल गांव में रहने वाले कारोबारी से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पीड़ित कारोबारी का पड़ोसी है और पूर्व में किरायेदार भी रह चुका है। पुलिस ने आरोपित के पास से रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया है।

इकलौते बेटे की हत्या की दी धमकी

आरोपित ने रंगदारी की रकम न देने पर कारोबारी के इकलौते बेटे को अगवा कर हत्या की धमकी दी थी।मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में डीसीपी ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित कड़कड़ माडल गांव का किश्चर कुमार नायक है। वह मूलरूप से ओडिशा का रहने वाला है, लेकिन बचपन से यहीं रह रहा है।

बीकाम पास किश्चर के पास से बरामद मोबाइल फोन बुलंदशहर से चोरी किया गया था, इसी मोबाइल से काल कर रंगदारी मांगी गई थी। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसे यह मोबाइल फोन चालू हालत में गाजियाबाद की किराना मंडी में पड़ा मिला था। किश्चर नायक ने इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल केवल रंगदारी मांगने के लिए ही किया था।

30 लाख रुपये की मांगी थी रंगदारी

काल करने के बाद उसने फोन का स्विच आफ कर लिया था, जिसके चलते उसे ट्रेस करने में पुलिस को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के जरिये उसका दूसरा नंबर खोज लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कड़कड़ माडल गांव के रहने वाले राजेश राघव से 31 जनवरी की रात फोन पर 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

उन्होंने मामले में एक फरवरी को लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि रंगदारी की रकम न देने पर इकलौते बेटे को अगवा कर हत्या करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने तत्काल उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया था।

आरोपित को प्लाट बिकने की थी जानकारी

डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि किश्चर नायक पूर्व में कारोबारी के घर में ही किराए पर रहता था। किश्चर ने कारोबारी के साथ मिलकर पूर्व में कारोबार भी किया था। लेकिन कोरोना काल में उनका धंधा बंद हो गया और उसके बाद किश्चर ने जो भी काम किया वह चल नहीं सका।

वर्तमान में वह चाउमीन की ठेली लगा रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपित को कारोबारी की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि कारोबारी ने कुछ समय पूर्व ही एक प्लाट बेचा है। उसे कारोबारी के पास करीब 75 लाख रुपये होने की जानकारी थी। इसके चलते उसने कारोबारी से रंगदारी मांगी।

सड़क हादसों में आएगी कमी, मेरठ रोड पर 16 ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म, ट्रैफिक पुलिस ने किया निरीक्षण

एनटीवी न्यूज

ट्रैफिक पुलिस ने पीडब्ल्यूडी व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान 16 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। सभी 16 प्वाइंट्स पर सड़क हादसे रोकने के लिए सुधार की योजना तैयार की गई है।

गाजियाबाद। मेरठ रोड पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस प्रयास कर रही है। वर्ष 2019, 2020 व 2021 में मेरठ रोड पर चिह्नित किए गए 16 ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना रोकने के लिए अब काम शुरू हुआ है।

ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सभी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया और यहां क्या सुधार किया जाए जिससे सड़क हादसों में कमी आ सके पर विचार किया।

एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस जिले में सड़क हादसों में कमी लोन के लिए प्रयास कर रही है। जल्द ही ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य कर इन्हें सही किया जाएगा, ताकि लोग सुरक्षित सफर कर सकें।

इन ब्लैक स्पॉट पर कराया जाएगा सुधार कार्य

घूकना मोड़ पर स्थित कट को बंद कर दोनों तरफ यू-टर्न बनाए जाएंगे।

दुहाई पुल के नीचे के कट को बंद कर यू-टर्न बनाने के साथ ही ईस्टर्न पेरीफेरल से तेज गति से मेरठ रोड की आने वाले वाहनों के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने व साइनेज बोर्ड लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही पेरीफेरल से उतरने वाले मार्गों को चौड़ा कराया जाएगा।

आइटीएस कट को बंद कर यू-टर्न बनाया जाएगा।

सैंथली गांव के सामने के कट के निकट टी-प्वाइंट कट को बंद कर तेजी से आने वाले वाहनों के लिए लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने के साथ साइज बोर्ड लगवाए जाएंगे।

हनुमान मंदिर के टी-प्वाइंट को बंद कर लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर व साइनेज बोर्ड लगवाने के साथ ही सड़क को चौड़ा किया जाएगा।

आर्डिनेंस फैक्ट्री कट को बंद कर यू-टर्न बनाया जाएगा। आर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से तेज गति से आने वाले वाहनों को मुख्य मार्ग पर पहुंचने से पहले ही स्पीड कम करने के लिए वहां स्पीड ब्रेकर व साइनेज बोर्ड लगवाए जाएंगे।

जलालपुर कट बंद कर पुलिया का चौड़ीकरण करा वहां यू-टर्न बनाए जाएंगे।

मुरादनगर बंबा कट पुलिया का चौड़ीकरण कर यू-टर्न बनाया जाएगा और लिंक रोड पर ब्रेकर व बोर्ड लगाए जाएंगे।

रावली रोड कट पुलिया का चौड़ीकरण कर टी-प्वाइंट को बंद किया जाएगा और मुख्य मार्ग पर लगे बिजली के खंभों को भी वहां से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।

गंग नहर मुरादनगर कट के डिवाइडर को और अधिक ऊंचा करने के साथ ही इस पर बने सभी कट को बंद कर गंग नहर लेफ्ट टर्न कट को और अधिक चौड़ा किया जाएगा। वहां बोर्ड और स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएंगे।

एडीसीपी यातायात रामानंद कुशवाहा ने बताया कि 16 ब्लैक स्पॉट को समाप्त कराने के लिए निरीक्षण कर योजना तैयार की गई है। सड़क सुरक्षा समिति में इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए जल्द निरीक्षण किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

इनसाइड

स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने लूटे 44 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस

गाजियाबाद। स्क्रैप कारोबारी से बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर 44 लाख रुपए लूट ले गए। घटना सोमवार देर रात की है। दिल्ली सीलमपुर से व्यापारियों से तगादा कर रूपये लेकर लौट रहे मुरादनगर निवासी स्क्रैप कारोबारी फरमान से बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर 44 लाख रूपये लूट लिए। वारदात के बाद बदमाशों की बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मौके से गुजर रहे मोरटी निवासी भूपेश से स्कूटी लूटकर फरार हो गए। फरमान अपने दोस्त आसिफ के साथ मुरादनगर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि जानकारी करने पर फरमान ने बताया सोमवार शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली से चले थे। करीब साथ बजे वह राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे। जाम की स्थिति को देखते हुए मोरटी कट से भट्टा नंबर पांच की ओर से जाने लगे। कच्चे रास्ते पर पहुंचते से पीछे से आए एक बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक बदमाश ने हथियार से चालक की ओर का शीशा तोड़ दिया और पैसे मांगने लगा। वहीं दूसरा बदमाश दूसरी ओर आया और दरवाजा खोलकर आसिफ के घुटने में तमंचे की बट मारी। गोली मारने की धमकी देकर बदमाश पैसों से भरा बैग लूटकर भाग गए। डीसीपी नगर जोन निपुण अग्रवाल ने बताया कि मामले में चार टीम का गठन कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

छेड़खानी से परेशान युवती ने छोड़ी नौकरी, पुलिस को दी शिकायत

नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने अपने साथ काम करने वाले एक सीनियर के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही लड़की ने इन सभी परेशानियों को चलते अपनी नौकरी भी छोड़ दी है।

नोएडा। एक रियल स्टेट कंपनी के सीनियर अधिकारी की छेड़खानी से तंग आकर वहां काम कर रही एक युवती ने नौकरी छोड़ दी और मामले की शिकायत सेक्टर-113 कोतवाली पुलिस से की।

आरोपित युवती को बीते कई माह से परेशान कर रहा था। मूलरूप से उन्नाव की एक युवती बीते साल 16 मई को नौकरी करने के लिए नोएडा आई और सेक्टर-56 में किराये का कमरा लेकर रहने लगी। युवती ने सेक्टर-75 स्थित एक रियल स्टेट कंपनी में बतौर सेल कंसलटेंट ज्वाइन किया।

पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि 16 मई से 22 दिसंबर तक उन्होंने संबंधित कंपनी में काम किया। कंपनी में सीनियर सलीम खान नाम का व्यक्ति युवती के साथ छेड़खानी कर अश्लील टिप्पणी भी करता था। बीते साल 12 नवंबर को सलीम ने जब युवती के कंधे पर हाथ रखा तो युवती ने इसका विरोध किया। इसके बाद सलीम आए दिन युवती को परेशान करने लगा। 22 दिसंबर को जब सलीम ने फिर से युवती के साथ छेड़खानी की तो युवती ने कंपनी छोड़ दी।

फोन कर परेशान करता था आरोपी: युवती

युवती का आरोप है कि कंपनी छोड़ने के बाद भी सलीम फोन पर परेशान करता है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। आरोपित युवती को अकेले मिलने के लिए भी बुलाता है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज र पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के बाद फरार हुआ आरोपित

युवती ने बताया कि उसके पिता किसान हैं और तीन बहनों में वह सबसे बड़ी है। बहनों की पढ़ाई का जिम्मा युवती पर ही है। नौकरी के साथ ही युवती बीएससी की पढ़ाई भी कर रही है। आरोप है कि इस मामले की शिकायत जब युवती ने कंपनी प्रबंधन से की, तो जबरन उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही आरोपित फरार है। डीसीपी महिला सुरक्षा डा. मीनाक्षी कात्यान ने बताया कि फरार आरोपित की तलाश जारी है।

ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कार पेड़ से टकराई, छात्र की मौत

ग्रेटर नोएडा स्थित डेल्टा 2 के पास गोल चक्कर के बैरीगेटिंग को तोड़कर एक कार पेड़ से टकरा गई जिससे कार सवार एक छात्र की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित नवादा गोल चक्कर पर हुए हादसे में 23 वर्षीय अक्षय प्रसाद की हुई मौत। वह एमिटी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। 5 घंटे तक अस्पताल में चला उपचार। तेज रफ्तार के चलते कार गोल चक्कर पर चढ़कर पेड़ से टकरा गई थी। सिर में अधिक चोट लगने और खून बहने की वजह से हुई मौत। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र का मामला। शुरुआती जानकारी के आधार पर ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 गोल चक्कर के पास एक अनियंत्रित कार गोल चक्कर की बैरीगेटिंग को तोड़ते हुए एक पेड़ से टकरा गई, जिससे एक कार सवार युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

नोएडा में पहली स्मार्ट पार्किंग सेक्टर-18 में होगी शुरू, घर बैठे बुक करा सकेंगे स्पेस

नोएडा के सेक्टर 18 में पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण जल्द ही एक स्मार्ट पार्किंग की तैयारियां शुरू करने वाला है। इस स्मार्ट पार्किंग के अंदर कई तरह की अधुनिक सुविधाएं होगी जिससे आप अपने घर बैठ हुए पार्किंग के लिए स्पेश बुक कर लेंगे।

नोएडा। शहर की सबसे बड़ी मार्केट और व्यवसायिक हब के रूप में पहचान बना चुके सेक्टर-18 में अब स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल आरएफपी जारी किया है। इसमें 24 फरवरी तक कंपनियां आवेदन कर सकेंगी। प्राधिकरण चाहता है कि सेक्टर-18 की पार्किंग ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलाजी आधारित सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर पर काम करेंगी। ये सेंसर बहुमंजिला पार्किंग के साथ ही सरफेस पार्किंग में भी लगाने होंगे। इन सेंसर के लगने के बाद पूरी पार्किंग रिमोट कंट्रोल के जरिये व्यवस्थित की जाएगी। जिस कंपनी को इस कार्य के लिए चुना जाएगा, उसे तीन माह में सभी सुविधाएं सेक्टर-18 की सभी पार्किंग में उपलब्ध करानी होगी।

सिस्टम लगाने वाली कंपनी को पांच वर्ष तक इसका संचालन और पूरे सिस्टम की देखरेख और अनुरक्षण का कार्य भी करना होगा। पार्किंग क्षेत्र में लगाए जाने वाले कैमरों के जरिये वहां होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर बहुमंजिला कार पार्किंग में बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। बताते चलें कि सेक्टर-18 की सरफेस पार्किंग में एक समय में 1062 कार और 279 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं।

बहुमंजिला कार पार्किंग में 2823 कार और 180 दो पहिया वाहन एक समय में खड़े होने की व्यवस्था है। दोनों तरह की पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग में बदलने में 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत होने के बाद लोग सेक्टर-18 में पहुंचने से पहले ही मोबाइल एप के जरिये अपने लिए पार्किंग में स्थान रिजर्व कर लेंगे। जिससे पार्किंग ढूंढने के झंझट से निजात मिलेगी और जिस जगह जाना है, उसके आसपास पार्किंग भी मिल जाएगी। जिस समय पार्किंग एप से बुक कराई जाएगी, उसी समय से वह रिजर्व हो जाएगी और उसी समय से पार्किंग की शुल्क भी लगना शुरू हो जाएगा।

पार्किंग की पहले से हो सकेगी बुकिंग

लोगों को नहीं होगी असुविधा: प्रबंधक

पार्किंग के बारे में नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक वीके रावल ने बताया कि सेक्टर-18 की पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पूरी पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग में तब्दील किए जाने की तैयारी है। इससे सेक्टर-18 में आने वाले लोगों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द कंपनी का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इनसाइड

Honda CB500F बाइक की दिखी पहली झलक, जल्द लॉन्च होने की उम्मीद, जानें किन फीचर्स से हो सकती है लैस

Honda CB500F Bike जल्द ही भारतीय ऑटो बाजार में देखने को मिल सकती है। इसे होंडा के एक डीलरशिप में देखा गया है। बता दें कि इसे ब्रांड के 500cc सेगमेंट में लाने की बात कही जा रही है और कई नए फीचर्स को देखा जा सकेगा।

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा जल्द ही अपनी एक नई बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु के एक होंडा डीलरशिप पर नई Honda CB500F बाइक को देखा गया है। कुछ समय पहले होंडा ने भारत में अपने नए 500cc प्लेटफॉर्म के आधार पर एक बाइक को लॉन्च करने की बात कही थी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में यह वही बाइक है, जिसके बारे में होंडा ने बात की थी।

मिल सकता है जबरदस्त पावरट्रेन

नई होंडा CB500F को नेकेड बाइक सेगमेंट में एक माइल्ड इंजन के साथ लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, इस बाइक में 471cc वाला पैरेलल ट्विन मोटर दिया जा सकता है, जो 600rpm पर 47.5PS की पावर और 6500rpm पर 43Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा।

ट्रांसमिशन के लिए बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स को भी जोड़ा जा सकता है। बता दें कि बिगविंग के लिए अपने 500cc पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए होंडा काफी समय से काम कर रही है। इस कारण होंडा की इस बाइक को लाये जाने की बात कही जा रही है।

बेहतर राइडिंग का मिलेगा अनुभव

नई होंडा बाइक को बेहतर राइडिंग का अनुभव देने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। इसमें 41mm के फ्रंट फोर्क और दोनों सिरों पर प्री-लोड-एडजस्टेबिलिटी के साथ एक रियर प्रो-लिंक मोनोशॉक शामिल किए जा सकते हैं। वहीं, ब्रेकिंग के लिए फ्रंट व्हील पर 320mm का डिस्क ब्रेक और 240mm रियर डिस्क देखने को मिल सकता है। इसके आलवा, डुअल-चैनल ABS ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए जोड़ा जा सकता है।

Honda CB500F की कीमत और लॉन्चिंग

Honda CB500F बाइक को भारत में अगले साल जून तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 4.79 लाख रुपये है। वहीं, लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Benelli Leoncino 500 बाइक से होगा।

नई Royal Enfield Super Meteor 650 से उठा पर्दा, जानें क्या हैं रेट्रो लुक वाली इस क्रूजर बाइक के फीचर्स

नई दिल्ली, । रॉयल एनफील्ड ने काफी लंबे समय से इंतजार की जा रही अपनी सुपर मीटियोर 650 (Super Meteor 650) बाइक से पर्दा उठा दिया है। इसे इटली में आयोजित 2022 EICMA शो में पेश किया गया है और उम्मीद है कि इसे इसी महीने भारत में होने वाली राइडर मेनिया इवेंट 2022 में भी शोकेस किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पेश हुई रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 एक क्रूजर बाइक है, जिसे रेट्रो लुक में उतारा गया है। इसके अलावा, इसमें 648cc वाले पैरेलल-ट्विन इंजन भी दिया गया है। इवेंट में सामने आई बाइक एक एक लो-प्रोफाइल बाइक है, जो काफी हद तक मीटियोर 650 की तरह ही दिखती है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम एलीमेंट्स को शामिल किया गया है। इसे टूरर ट्रिम में एक लंबी विंडस्क्रीन, एक पिलर बैकरेस्ट, ड्यूल सीट्स, पैनियर, एक टूरिंग हैंडलबार और बड़े फुटपेग जैसे कई बिट्स मिलते हैं। साथ ही बाइक में 1,500mm का लंबा व्हीलबेस देखने को मिलता है।

Hyundai Grand i10 Nios से लेकर Tata Punch सात लाख के अंदर मिलती हैं ये शानदार गाड़ियां

भारत में कई शानदार कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें सात लाख रुपये कर बजट में खरीदा जा सकता है। इसलिए अगर आप इन दिनों ऐसी कोई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस लिस्ट को देखें।

नई दिल्ली। अगर आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो दिखने में शानदार हो, कई फीचर्स से लैस हो, लेकिन आपके बजट में भी आ जाए तो सात लाख रुपये के अंदर भारत में कई शानदार कारें उपलब्ध हैं। इसमें हुंडई की नई ऑरा और ग्रैंड i10 निऑस से लेकर टाटा पंच और निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियां शामिल हैं। तो चलिए इस रेंज में आने वाली गाड़ियों को देखते हैं।

Hyundai Grand i10 Nios Facelift

हुंडई ग्रैंड i10 निऑस फेसलिफ्ट गाड़ी को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 5.58 लाख रुपये रखी गई है और इसमें नया आरडीई कंप्लेंट 1.2-लीटर एनए पेट्रोल इंजन मिलता है । मैनुअल गियरबॉक्स के साथ इस गाड़ी में 20.7 kmpl और AMT के लिए 20.1 kmpl की माइलेज देने की क्षमता है। इसके अलावा, अलावा CNG विकल्प मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए सीएनजी वेरिएंट में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

Hyundai Aura Fecelift

सात लाख रुपये के बजट में हुंडई के पास नई ऑरा फेसलिफ्ट सेडान कार भी है। यह कार में 1.2-लीटर इंजन के साथ आती है, जो 83hp की पावर और 113.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ऑरा फेसलिफ्ट के बेस मॉडल को 6.29 लाख रुपये में पेश किया गया है जो कि टॉप मॉडल के लिए 8.57 लाख रुपये तक जाता है।

Tata Punch

सात लाख रुपये से कम बजट वाली कारों में टाटा पंच कार भी है। इसकी कीमत 6.00 लाख रुपये से 9.54 लाख रुपये के बीच है। इस कार में 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है, जो 84.48bhp की पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बहुत-से फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं।

Nissan Magnite

इस लिस्ट में आखिरी कार निसान की मैग्नाइट है। निसान मैग्नाइट के बेस 'एक्सई' वेरिएंट की कीमत 5.97 लाख रुपये है। इस कार में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड मॉडल है जो 71.05bhp की पावर जनरेट करता है। साथ ही, एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इस कार में चार्जर, एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं भी हैं।

मिनी कूपर कनवर्टिबल एस कार खरीदने के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली, कंपनी ने बढ़ाए इतने रुपये तक दाम

Mini Cooper Convertible S की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। अब मिनी कूपर को खरीदने के लिए आपको 5.32 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं इस कार में 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है जो कि 16 kmpl की माइलेज दे सकता है।

नई दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी मिनी इंडिया ने अपनी मिनी कूपर कनवर्टिबल एस कार की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमतों में 5.32 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि मिनी कूपर को पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था और इसमें 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है।

Mini Cooper की नई कीमत

कीमत की बात करें तो जब इसे जून 2021 में लॉन्च किया गया था तब मिनी कूपर की कीमत 44 लाख रुपये थी, लेकिन अब बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 51.82 लाख रुपये हो गई है। वहीं, इसके बाकी मॉडल की कीमत फिलहाल पहले की तरह ही है।

Cooper Convertible S का पावरट्रेन

कंपनी ने इसमें 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया है। यह इंजन 192bhp की पावर और 280Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। साथ ही यह 7-स्पीड डुअल क्लच DCT स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अलावा, 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस कन्वर्टिबल को 7.1 सेकंड का वक्त लगता है और यह 16 kmpl की माइलेज दे सकती है।

Mini Cooper SE भी है बिक्री के लिए उपलब्ध

जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में Mini Cooper SE भी बिकक्री के लिए उपलब्ध है। यह एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें 32.6 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है और यह 184bhp की पावर और 270Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। रेंज की बात करें तो एक बार चार्ज करने पर यह 235 से 270 किमी की रेंज देती है और 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार महज 7.3 सेकेंड में पकड़ सकती है।

EV सेगमेंट में छाएगा रॉयल एनफील्ड का जादू, 2024 में होगी नई बाइक की एंट्री

रॉयल एनफील्ड अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक को साल 2024 में लॉन्च कर सकती है। इसे L सीरीज के तहत लाया जा सकता है और एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बन सकता है।

नई दिल्ली। बुलेट निर्माता रॉयल एनफील्ड ने कुछ समय पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि कंपनी जल्द इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एंट्री ले सकती है। इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब खबर है कि रॉयल एनफील्ड की नई बाइक अगले साल तक दस्तक दे सकती है। इसे फिलहाल कोडनेम 'L' कहा गया है और इसके बारे में कुछ जानकारी लीक हुई है।

पेश हो सकता L रेंज

कहा जा रहा है कि बाइक निर्माता जल्द ही Lकोडनेम वाली पूरी एल सीरीज को पेश कर सकती है। इसके प्रोडक्ट को L1A, L1B और L1C नाम से जाना जा रहा है और ये बिल्कुल नए प्रोडक्ट हो सकते हैं।

रफ एंड टफ लुक में आ सकती बाइक

पहले मिली जानकारी के मुताबिक, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक आक्रामक दिखती है और इसे डर्ट-बाइक के रूप में भी लाया जा सकता है। नियो-विंटेज लुक के साथ अपकिंग बाइक हाई क्वालिटी के टैक्टाइल फिनिश और टच पॉइंट्स के साथ आ सकती है। ब्रांड का खास गोल हेडलैम्प और फ्यूल टैंक अब भी बरकरार रहेगा और मोनो-शॉक सस्पेंशन सेटअप के साथ डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं।

Royal Enfield Electric Bike का पावरट्रेन

पावरट्रेन के रूप में रॉयल एनफील्ड को इसके ICE इंजन के समान पावर का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 250 से 300cc तक का पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए खास प्लेटफॉर्म को भी बनाया जा सकता है, जो स्पैनिश इलेक्ट्रिक डर्ट-बाइक निर्माता स्टार्क फ्यूचर से साझेदारी के तहत लिया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इसमें कौन-कौन से लेटेस्ट फीचर्स को शामिल किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति

डा. अश्विनी महाजन,

आज जब बड़े विकसित देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति के बलबूते दूसरे मुल्कों पर शर्तें और प्रतिबंध लगाने की कोशिश में लगे हैं, भारत अपनी स्वतंत्र आर्थिक, सामरिक और विदेश नीति के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने की इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है।

आज जब भारत समेत पूरी दुनिया महंगाई की मार से पीड़ित है, अमरीका और यूरोपीय देशों के मुकाबले ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों की तुलना में भारत में महंगाई की दर काफी कम बनी हुई है। गौरतलब है कि यूरोपीय समुदाय के देशों में दिसंबर माह में महंगाई की औसत दर 10.4 प्रतिशत बनी हुई थी, जिसमें हंगरी में 25 प्रतिशत, पोलैंड में 15.3 प्रतिशत, इटली में 12.3 प्रतिशत, नीदरलैंड में 11 प्रतिशत, आस्ट्रिया में 10.5 और पुर्तगाल में 9.8 प्रतिशत थी। उसी प्रकार अमरीका में महंगाई की दर अभी भी 6.5 प्रतिशत बनी हुई है, जबकि इससे पहले वो जून 2022 में 9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसी प्रकार दुनिया के अधिकांश मुल्क भीषण महंगाई की चपेट में हैं। दुनिया में बढ़ती इस महंगाई के पीछे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। हालांकि अमरीकी अर्थव्यवस्था तेल की वैश्विक कीमतों से प्रभावित नहीं होती, तो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे तेल के कारण अमरीका में महंगाई बढ़ी है। यूरोप में ऊर्जा (यानी तेल, पेट्रोल इत्यादि) में महंगाई 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, इसके अलावा यूरोप में महंगाई बढने का दूसरा बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि है। लेकिन भारत में मुद्रास्फीति जो पहले भी अमरीका और यूरोप से कम थी, दिसंबर माह में घटकर 5.72 प्रतिशत ही रह गई है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है।

भारत द्वारा रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना बाजार के कारण नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के कारण संभव हुआ है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार महंगाई दर बढने का पहला असर ब्याज दरों पर पड़ता है। और ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक संवृद्धि में बाधा आती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमरीका और यूरोपीय देशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया के अधिकांश मुल्कों द्वारा रूस से तेल और गैस की खरीदी प्रभावित हो गई। अमरीका और यूरोपीय देशों ने यह शर्त लगा दी कि रूस से तेल और गैस खरीदने पर बैंकिंग चैनल अवरुद्ध कर दिया जाएगा और वे देश भुगतान नहीं कर पाएंगे। यही नहीं नवंबर में अमरीका और यूरोपीय देशों ने रूस द्वारा बेचे गए तेल की न्यूनतम कीमत की शर्त लगा दी और कहा कि किसी भी हालत में रूस दूसरे मुल्कों को उस न्यूनतम कीमत से सस्ता नहीं बेचने दिया जाएगा। अमरीका और यूरोपीय देशों का स्विफ्ट भुगतान व्यवस्था पर एकाधिकार है और इसको वे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत ने अमरीका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को धत्ता दिखाते हुए यह कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखा। गौरतलब है कि भारत रूस से आज 33.28 डालर के डिस्कांउट पर तेल खरीद रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि अमरीका के अगुवाई वाले जी-7 राष्ट्रों द्वारा लगाई गई न्यूनतम तेल कीमत यानि 60 डालर प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर ही भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यानि जी-7 की यह शर्त भारत को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक पाएगी। यूरोपीय देशों ने जब यह प्रतिबंध लगाया कि रूस से तेल खरीदने की सूरत में पश्चिमी देशों की जहाजों और बीमा सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, तो भारत ने कहा कि हम गैर पश्चिमी पोत सेवाओं से ही रूस से तेल मंगा लेंगे। जहां तक बैंकिंग चैनलों पर प्रतिबंध का सवाल है, भारत और रूस से आपसी लेन-देन स्विफ्ट के उपयोग के बिना करने का तय किया। भारत और रूस में यह भी सहमति बन गई कि आगे चलकर भारत और रूस रुपए और रूबल में व्यापार कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जहां तेल उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा रखने के लिए अपने उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, रूस भारत सरीखे एशियाई देशों, जो अमरीका और यूरोप के प्रभाव में नहीं हैं, को तेल बेच रहा है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को अहमियत देता है और इस कारण से वो रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा।

गौरतलब है कि भारत अप्रैल माह में युद्ध से पूर्व तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर 35 डालर प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा था। रूस द्वारा भारत को यह आकर्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि उसे मालूम था कि केवल भारत ही रूस से तेल खरीद सकता है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र विदेश नीति में विश्वास रखता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने दोहरे मापदंड अपनाते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। उधर भारत और कुछ अन्य देशों को तेल बेचते हुए रूस का तेल का बाजार बना रहा। इसका असर यह हुआ कि जहां दुनिया के दूसरे मुल्क 100 डालर से भी महंगा तेल खरीद रहे थे, भारत 33 से 35 डालर के डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीद रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021-22 में भारत का कुल तेल के आयात का बिल 119 अरब डालर था और युद्ध और अन्य कारणों से तेल की बढ़ती कीमतों के चलते इस साल यह बिल कहीं ज्यादा हो सकता था। लेकिन भारत द्वारा अमरीका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि उसमें खासी वृद्धि भी की। भारत अपने कुल तेल जरूरतों का मात्र 0.2 प्रतिशत ही रूस से खरीदता था, नवंबर 2022 तक आते-आते यह खरीद 909403 बैरल पहुंच गई जो भारत की कुल तेल खरीद का 20 प्रतिशत से ज्यादा था। भारत से रूस का तेल का आयात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर 7 को विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में स्पष्ट रूप से यह कहा कि भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां से उसे सस्ता मिलेगा। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपनी कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते, लेकिन कंपनियां वहीं से खरीदेंगी जहां से उनको सबसे सस्ता मिलेगा। उधर यूरोपीय देश भारत की यह कहकर आलोचना करते हैं कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध में गलत का साथ दे रहा है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया हुआ है और यूरोपीय प्रतिबंध उसे सबक सिखाने के लिए हैं।

भारत का कहना है कि एक तरफ तो भारत कहीं से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उसे अपने हितों की सुरक्षा करनी है। यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए भारत का कहना है कि वे स्वयं तो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं और भारत को रूस से तेल न खरीदने की शिक्षा दे रहे हैं। भारत के मंत्री हरदीप पुरी ने यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा कि भारत पूरे महीने में इतना तेल रूस से नहीं खरीदता जितना वे (यूरोपीय देश) एक शाम को खरीद लेते हैं, यानि भारत को यूरोपीय देश नैतिक ज्ञान नहीं दे सकते। इससे पहले जब अमरीका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे तो यह समझते हुए भी कि भारत को ईरान से तेल खरीदने पर फायदा हो सकता है, अमरीका के दबाव में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की ईरान से तेल खरीदने की ढुलमुल नीति रही और लम्बे समय तक भुगतान न करने के करण भी ईरान से तेल आयात बाधित रहा। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान से तेल खरीद में इजाफा करने की ओर कदम बढ़ाया है। आज जब बड़े विकसित देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति के बलबूते दूसरे मुल्कों पर शर्तें और प्रतिबंध लगाने की कोशिश में लगे हैं, भारत अपनी स्वतंत्र आर्थिक, सामरिक और विदेश नीति के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने की इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। यही स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हमारे विकास और समृद्धि का आधार बन सकती है।

संपादक की कलम से

'ओम-अल्लाह' का धर्मयुद्ध

ओम और अल्लाह एक ही हैं। मनु और आदम भी एक ही हैं। मनु की संतानें 'मनुष्य' कही गईं और आदम की औलाद को 'आदमी' कहा गया। अल्लाह ने आदम को भारत की ज़मीं पर भेजा, लिहाजा भारत मुसलमानों का पहला वतन है और इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है। जिसे हम 'अल्लाह' मानते हैं, वह ही हिंदुओं में 'ईश्वर' है, फारसी में उसे ही 'ख़ुदा' कहते हैं और ईसाई 'गॉड' मानते हैं। जब मनु धरती पर आए, तब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु और शिव भी नहीं थे, श्रीराम भी नहीं थे, तो मनु किसकी पूजा करते थे? किसी धर्मगुरु ने बताया कि मनु 'ओम' को पूजते थे। फिर सवाल उठा कि 'ओम' क्या था? किसी धर्मगुरु ने व्याख्या की कि 'ओम' का कोई रंग-रूप नहीं था। वह एक 'हवा' थी। जिसे आप 'हवा' मानते हैं, वही हमारे लिए 'अल्लाह' है। तमाम मुसलमानों को 'हिंदू' ही मानने वालों का विचार 'जाहिल' है। बहरहाल 21वीं सदी में धर्म और भगवान या अल्लाह की ऐसी स्थापनाएं हास्यास्पद लगती हैं। कोई विधर्मी, धूर्त और अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसी व्याख्याएं कर सकता है या किसी के विचार को 'जाहिल' करार देते हुए गाली दे सकता है। मुसलमानों के सबसे पुराने और व्यापक मज़हबी और सामाजिक संगठन 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' के मंच से वयोवृद्ध मौलाना अरशद मदनी ने धर्म और परमात्मा संबंधी ऐसी व्याख्याएं कर साबित करने की कोशिश की है कि भारत 'धर्मनिरपेक्ष देश' नहीं है। बेशक संविधान में धार्मिक और पूजा-पाठ पद्धति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, लेकिन दूसरे के धर्म और आस्थाओं को गाली देने और उसे अधम करार देने का अलिखित अधिकार भी दिया गया है। बुनियादी तौर पर भारत को मुसलमानों का वतन कहा गया है। इस्लाम और मुसलमान भारत की ही पैदाइश हैं, वे कहीं बाहर से नहीं आए, ये स्थापनाएं भी दी गई हैं। जमीयत का यह आम आयोजन 'सर्वधर्म समभाव और सौहाद्र' की सार्वजनिक सोच के तहत किया गया था, लेकिन वह आडंबर और मुखौटा ही थे, नतीजतन जैन मुनि, सिख धर्मगुरु और अन्य को मंच छोड़ कर जाना पड़ा। स्पष्ट कर दें कि हम न तो धर्मगुरु हैं और न ही धर्मों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जितना भी अध्ययन किया है, उसके मुताबिक इन व्याख्याओं को खंडित किया जा सकता है। मौलाना मदनी ने विश्व के सनातन धर्म को खारिज किया है, जिसके कालखंड में वेदों, पुराणों और उपनिषदों के दर्शन दुनिया के सामने आए। मौलाना ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सरीखे ब्रह्मांड के 'दैवीय त्रिदेवों' और विष्णु-अवतार प्रभु श्रीराम के अस्तित्व को ही नकारा है, लिहाजा एक बहुसंख्यक मानवीय आबादी की धार्मिक आस्थाओं को कुचला गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का नाम ही नहीं लिया गया, जिनके सुपुत्र भरत के नाम पर देश का नामकरण 'भारत' किया गया था। उनका कालखंड ही करीब 3000 साल पुराना है। 'त्रिदेव' तो ब्रह्मांड के 'आदि रचयिता' हैं, लिहाजा उनके कालखंड की तो कल्पना की जा सकती है, व्याख्या असंभव है। अध्यात्म और आस्था तर्कों के आधार पर तय नहीं किए जा सकते। फिर इस्लाम धर्म तो 1600 वर्ष पुराना ही है, तो उसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कैसे माना और कहा जा सकता है? मौलाना भी धर्म के विशेषज्ञ नहीं हैं। अलबत्ता वह किसी भी मकसद और मंसूबों के तहत मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अरशद इस्लाम के कुछ जानकार हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म को लेकर वह 'शून्य' हैं।

विचार यात्रा के पड़ाव

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

भारतीय जनसंघ की स्थापना राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के आधार पर हुई थी। उस समय देश में कांग्रेस का वर्चस्व था। यह माना जाता था कि जनसंघ को विपक्ष की ही भूमिका का निर्वाह करना है। तब सदन में इसका संख्याबल कम होता था, लेकिन वैचारिक ओज प्रबल था। भारी बहुमत की सरकारें भी नाम मात्र के संख्याबल के विचारों से परेशान थीं। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जब संसद में बोलते थे, तब लोग ध्यान से सुनते थे। सरकार को भी कई मसलों को सुधारने संभालने की प्रेरणा मिलती थी। जनसंघ और भाजपा की यात्रा में अटल-आडवाणी की जोड़ी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जनसंघ के दौर में हिन्दुत्व के मुद्दों को मुखर होकर उठाया जाता था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। इन मुद्दों ने जनसंघ को हिन्दी भाषी राज्यों तक सीमित रखा। यहां भी जनसंघ सत्ता से बहुत दूर रही। गैर कांग्रेसवाद अभियान के समय कुछ प्रांतों में संविद सरकारें बनी थीं। जनसंघ उसमें शामिल थी। यह विचार यात्रा का दूसरा पड़ाव था। जनता पार्टी में जनसंघ के विलय एक नया पड़ाव था। आपातकाल के बाद की परिस्थिति में यह विलय अपरिहार्य हो गया था। अन्य पार्टियों के साथ चलने की विवशता थी। लेकिन जनसंघ घटक के लोग अपनी मूल विचारधारा से कभी विमुख नहीं हुए थे। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू की भांति दिखाने संबन्धी चर्चा शुरू हुई थी। किन्तु जनता पार्टी का प्रयोग ढाई वर्ष तक भी नहीं चला। इसके बाद जनसंघ घटक ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। इसमें गांधीवादी समाजवाद की अवधारणा समाहित थी। यह भी विचार यात्रा का एक पड़ाव था। इसमें भी भाजपा ने जनसंघ के समय के अपने मुद्दों का परित्याग नहीं किया था।अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण आंदोलन ने भाजपा को नए पड़ाव पर पहुंचाया। इसके बाद भी उसे अपने दम पर बहुत नहीं मिला। ऐसे में कुछ कशमकश था। गठबंधन की सरकार बनाने या फिर विपक्ष में ही बैठने का विकल्प था। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने का व्यावहारिक निर्णय हुआ। यदि ऐसा न होता तो उन मतदाताओं को निराशा होती जिन्होंने शायद पहली बार भाजपा को इतना बड़ा समर्थन दिया था। वाजपेयी की सरकार करीब दो दर्जन पार्टियों के समर्थन पर आधारित थी। ऐसे में वैचारिक मुद्दों पर अमल सम्भव नहीं था। फिर भी छह वर्षों तक चली इस सरकार ने सुशासन की मिसाल कायम की। विकसित भारत की मजबूत बुनियाद का निर्माण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की राजनीति भी बेमिसाल रही है। करीब आधी शताब्दी तक अटल बिहारी आगे चलते रहे। आडवाणी स्वेच्छा से पीछे रहे। संगठन के कार्य में संलग्न रहे। यह राजनीति की बेमिसाल जोड़ी थी। वह पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार को अपेक्षित सहयोग करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे। आडवाणी की रथयात्राओं ने भाजपा को नए मुकाम पर पहुंचाया। वस्तुतः भाजपा की यात्रा एक विचार की यात्रा रही है, जिसके आधार पर भाजपा का 'पार्टी विद अ डिफरेंस' का दावा एकदम सही लगता है। आज यह देश का सबसे लोकप्रिय दल है और इसकी विचारधारा जन-जन तक पहुंच चुकी है। भाजपा वर्तमान राजनीति में एक मात्र पार्टी है जो व्यक्ति या परिवार पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इस विचारधारा के आधार पर ही ऐसे अनेक मसलों का समाधान हुआ है, जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। भाजपा की सरकारें सुशासन के प्रति समर्पित रहती हैं क्योंकि यही उनकी विचारधारा है।

पर्यटन की नई बस्तियां

संकल्पों के रथ को विजयी बनाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली यात्रा की सुर्खियां ईमानदार और प्रभावशाली वकालत कर रही हैं। हिमाचल को ढांचागत विकास के लिए केंद्र का हाथ चाहिए और इसलिए सरकार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके अपना पक्ष मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री स्पष्टता से यह जानते हैं कि अगले पांच सालों के रिपोर्ट कार्ड में केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से क्या मांगना है या पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के राष्ट्रीय खाके में हिमाचल को कैसे उभारना है। केंद्र सरकार से हिमाचल के रिश्तों की पैरवी भले ही हर सरकार के दौर में हुई हो, लेकिन इस बार योजना प्रारूप, संकल्प, लक्ष्य तथा इच्छा शक्ति का स्तर एक अलग भूमिका में परिलक्षित हो रहा है। अब तक के फैसलों की फेहरिस्त में सरकार की इच्छा शक्ति देखें, तो तमाम राजनीतिक गारंटियों के बावजूद ऐसे संकल्प सामने आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ग्रीन राज्य की बुनियाद पर पर्यटन की नई बस्तियां ढूंढ रहे हैं। फोरलेन व अन्य सडक़ परियोजनाओं के अलावा अगर एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में सफलता मिलती है, तो पर्यटन के कई अनछुए पहलू उजागर होंगे। इस दिशा में वाइब्रेंट विलेज, धार्मिक तथा धौलाधार पर्यटन की शिनाख्त में एक बड़ा प्रयास निश्चित है। जाहिर तौर पर 'विलेज टूरिज्म' के रास्ते हिमाचल अपनी खासियत, प्राकृतिक संपदा, लोक संस्कृति, ग्रामीण आर्थिकी व दस्तकारी को भी नए आयाम तक पहुंचा सकता है। इसी तरह धौलाधार पर्यटन के माध्यम से संभावनाओं की तलाशी, पूरे उद्योग की स्थिति बदल सकती है। ऐसा एक प्रयास शांता कुमार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी शुरू हुआ था, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। अब टेंट सिटी को लेकर धौलाधार क्षेत्र में पर्यटन के खजाने का फिर से पता खोजा जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार पर्यटन को कांगड़ा के मार्फत विकसित होते देखा जा रहा है, तो नई परियोजनाओं के सिंहासन पर आशाएं विराजित हो रही हैं।

मसलन अगर गरली-परागपुर के समीप गोल्फ कोर्स स्थापित करने में सरकार की मेहनत रंग लाती है, तो इसके आगामी कदमों में कालेश्वर धाम का विकास तथा धरोहर गांव के संरक्षण में प्रदेश की पहली फिल्म सिटी रूपांतरित हो सकती है। हालांकि कांगड़ा जिला इससे पूर्व घोषित रूप से शीतकालीन व खेल राजधानी जैसी उपमाओं से नवाजा जा चुका है, लेकिन लोग आज तक पलक पांवडे बिछा कर केवल इंतजार ही करते रहे हैं। दरअसल कांगड़ा को केवल जिला के रूप में देखने के बजाय इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ते हमीरपुर, ऊना, चंबा तथा साथ लगते मंडी को नई संभावनाओं से देखें तो कई ट्रैवल या टूरिज्म सर्किट बन जाएंगे। हिमाचल के पर्यटन की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ उन तमाम परंपराओं को भी निखारना होगा, जो वर्षों से हमारे साथ प्रदेश की बहुरंगी तस्वीर में रंग भर रही हैं। प्रदेश के मेलों, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोहों को इनकी समग्रता में देखने का प्रयास ही नहीं हुआ, वरना शिवरात्रि, नलवाड़ी, मिंजर, दशहरा व रेणुका जी के वार्षिक समारोहों के अलावा ग्रामीण मेलों पर आधारित पर्यटन, अपने साथ व्यापारिक मेलों का शृंगार भी कर सकता है। जरूरत है एक ऐसे मेला विकास प्राधिकरण के गठन की, जो तमाम ग्रामीण व सांस्कृतिक मेलों का कुशलता पूर्वक संचालन करते हुए इन्हें हिमाचली आर्थिकी के पथ पर खड़ा करे। ये तमाम छोटे-बड़े मेले अपने वार्षिक आयोजनों में दो-ढाई सौ करोड़ की आय-व्यय को सीमित परिधि में गंवा रहे हैं, जबकि राज्य स्तरीय खाके में अगर मेला प्राधिकरण इनका विस्तार तथा संचालन करे, तो लोक कलाओं व लोक गीत-संगीत के माध्यम से न केवल कलाकारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि कुश्तियों के आयोजन आगे चलकर खेल प्रतिभा को चमकाने का स्थायी प्रबंध भी कर सकते हैं। प्रदेश स्तरीय ढांचे तथा सोच में बदलाव लाते हुए अगर विभागीय समन्वय से योजनाएं बनें, तो प्रदेश के परिवहन, वन, जलशक्ति, ऊर्जा, खेल, कला, भाषा एचं संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन तथा प्रशासन आपसी तालमेल से ढांचागत उपलब्धियों के अलावा पर्यटन संस्कृति को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल यह तो मानना ही पड़ेगा कि सुक्खू सरकार अपने इरादों से, संभावनाओं के हर क्षेत्र को छूना चाहती है और इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में हो रही मुलाकातें अपना खास असर रखती हैं।

पानी को बनाया नहीं, सिर्फ बचाया जा सकता है

उमाशंकर पांडेय

पानी को बनाया नहीं बल्कि इसे केवल बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जखनी गांव की हरियाली सारी दुनिया के लिए उदाहरण है। यहां के मेड़बंदी मॉडल को जल संरक्षण के लिए सारे देश में कई जगह लागू किया जा चुका है। भारत का जल शक्ति मंत्रालय इसे पूरे देश के लिए उपयुक्त मानते हुए हर जिले में दो गांवों को जखनी जैसा जलग्राम बनाने के लिए चुन चुका है। नीति आयोग ने भी इस जल संरक्षण विधि को मान्यता दी है और इस आधार पर जखनी को आदर्श गांव माना है। लोग जागरूक हों तो सूखा और अकाल आ ही नहीं सकता। हमें अपने पूर्वजों के समाधान को अपनाना होगा। पुराने तालाबों और कुंओं का जीर्णोद्धार करना होगा। खेतों की मेड़बंदी कर घरों की नालियों का पानी भी खेतों में पहुंचाना होगा।

हमारे पुरखों की जल संरक्षण पर सोच 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' रही है। इसी सोच ने जखनी के जख्म सोख लिए हैं। जखनी के लोगों की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं। मगर इस बदलाव के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह एक दिन में संभव नहीं होता। जखनी को हरा-भरा करने के सामुदायिक प्रयास में दो-ढ़ाई दशक लग गए। अब हमारा गांव गरीबी, भुखमरी, अपराध और तमाम विवादों से उबर चुका है। वर्षा जल बूंदों को रोकने से गांव का जलस्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि गांव में समृद्धि आई और लोगों के पास पैसा आया। अब दुनिया के लोग इस तकनीक को जानने के लिए उत्सुक हैं।

पिछले दिनों अहमदाबाद में इस तकनीक पर कई सत्र में चर्चा हुई। यह देखकर अच्छा लगा कि अपना जखनी आज दुनिया को राह दिखा रहा है। यहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, इटली और यूरोप के लोगों से मिलने का मौका सुखद रहा। यह लोग जखनी मॉडल को जानना-समझना चाहते हैं। मोयेज पूनावाला (ऑस्ट्रेलिया), थॉम हन्ना (यूएसए), वेन मेयर (यूएसए), ओलिवियर गिलोटो (फ्रांस), तोशियो मुरामात्सु (जापान), ब्रूनो बेनाग्लिया (इटली) जेम्स वैलियरे (यूएसए), यूसुफ अत्तरवाला (फोराड) गुजरात, जॉनसन स्क्रीन के ग्लोबल डायरेक्टर क्रेक्स विल्सन (अमेरिका), राकेश अरोरा (पंजाब), विवेक सिंह (भूटान) अनिल शाह (पूना) और सीजीडब्ल्यूबी (जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरसी जैन ने गंभीरता के साथ भारत के पुरखों की परंपरागत सामुदायिक जल संरक्षण विधि 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' के चमत्कार को सुनकर दंग रह गए। दुनिया के विकसित देशों के इन जल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने माना कि जल संकट से घिरी दुनिया को यह विधि उबार सकती है। खुशी इस बात की है कि इजरायल में तो काफी पहले इस विधि पर परीक्षण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का 'बुंदेलखंड' हर साल गर्मी में सूखे और अकाल से त्राहिमाम-त्राहिमाम करता रहा है। खुशी इस बात की है कि अब हालात बदल रहे हैं। जखनी गांव के लोगों के तीस साल के सामुदायिक प्रयास से सूखा खत्म हो गया है। खेत हर वक्त लहलहाते रहते हैं। अब तो हर साल मेड़बंदी यज्ञ यात्रा भी होने लगी है। प्रधानमंत्री के सकारात्मक संदेशों से जखनी के मूलमंत्र 'खेत पर मेड़-मेड़ पर पेड़' को जल आंदोलन के रूप में बदला जा सका है। यह वही बुंदेलखंड है जहां कभी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ का आगाज किया था। यह सुखद है कि उसी बुंदेलखंड में मेड़बंदी यज्ञ शुरू होने लगा है। मेड़ बंदी से जल रोकने का उल्लेख मत्स्य पुराण, जल संघिता, आदित्य स्त्रोत के अलावा वेदों में भी खासकर ऋग्वेद में है। कालखंड बेशक बदला है पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। मगर यह सुनकर क्षोभ होता है कि दुनिया भर में 320 करोड़ लोग पानी की कमी वाली जगहों पर रहते हैं।

प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी

प्रताप सिंह पटियाल

जल प्रबंधन की परिपाटी का उच्च स्तर तथा धार्मिक गौरव व आध्यात्मिक महत्त्व को समेटे मुकद्दस पारंपरिक जलस्रोतों का अस्तित्व बचाना होगा। पुरखों की अमूल्य विरासत पेयजल तंत्र की उत्तम व्यवस्था पनघट संस्कृति के जीर्णोद्धार के लिए यदि सरकारी दरवाजे खुले तो जल संकट का यकीनी तौर पर समाधान हो सकता है'

देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने जिन व्यापक संसाधनों से नवाजा है उनमें सबसे अमूल्य सौगात प्राकृतिक जलस्रोत हैं। प्रदेश में बहने वाली नदियों, खड्डों व प्राकृतिक जलस्रोतों के पानी से पड़ोसी राज्यों की पेयजल सहित सिंचाई की जरूरत भी पूरी हो रही है। निःसंदेह हम अपने पुरखों की कई गौरवशाली परंपराओं के वारिस रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि आधुनिकता की चकाचौंध में पूर्वजों की उन गौरवमयी परंपराओं व रीति-रिवाजों को उपेक्षित करके पश्चिमी तहजीब की दहलीज पर खड़े होने की पुरजोर कोशिश हो रही है। जम्हूरियत के मौजूदा निजाम में इसे विकास कहें या आधुनिकता का खुमार, यह निश्चित तौर पर मंथन का विषय है। गर्मी का मौसम दस्तक देते ही जल संपदा के धनी राज्य हिमाचल को भी पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ता है। दुनिया को पानी का महत्त्व समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1993 से 20 मार्च के दिन को 'विश्व जल दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की है। मगर सनातन संस्कृति के पौराणिक ग्रंथों में जल व जलाशयों की महिमा का विशेष उल्लेख हुआ है। धार्मिक मान्यताओं में जलस्रोतों को देवतुल्य तथा जल संरक्षण को सर्वोपरि पुण्य कार्य माना गया है। मकर पर विराजमान 'वरुण देव' की जल देवता के रूप में पूजा की जाती है। सन् 2010 में जल दिवस के मौके पर यूएनओ के तत्कालीन सरवराह 'बान की मून' ने कई राष्ट्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल ही जीवन है। मगर भारतीय सभ्यता में 'जल ही जीवन है' का सिद्धांत अनादिकाल से ही प्रतिपादित है।

पैदल यात्रा करने वाले राहगीरों के लिए पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था 'प्याऊ संस्कृति' प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों का पुण्य सरोकार विश्व के लिए अनूठा उदाहरण है। महर्षि 'याज्ञवल्क्य' ने 'शतपथ ब्राह्मण' ग्रंथ में 'आपो वै प्राणः' प्रसंग के माध्यम से जल को प्राण की संज्ञा दी है। हमारे ऋषियों ने पंच तत्त्वों में जल को सबसे विशिष्ट महत्व देकर अमृत से तुलना की है। मगर अफसोस कि अमृत समझे जाने वाले प्राकृतिक जलस्रोतों का शुद्ध जल प्रदूषण का दंश झेल रहा है तथा करोड़ों आबादी की प्यास बुझाने वाले पारंपरिक जलस्रोत अपने वजूद को तरस रहे हैं। भूजल के सतत प्रबंधन को अहमियत देने के लिए भारत सरकार ने सन् 1987 में पहली 'राष्ट्रीय जलनीति' का मसौदा तैयार किया था। जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए अप्रैल 2002 में दूसरी राष्ट्रीय जलनीति बनाई गई। जल संकट को गंभीर खतरा मानते हुए पानी के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु 2012 में तीसरी राष्ट्रीय जलनीति के तहत पानी के निजीकरण को विस्तार दिया गया। भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास प्रबंधन के लिए सन् 1970 में केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। पानी की गंभीर चुनौतियों से निपटने तथा लोगों को पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए 'जल शक्ति मंत्रालय' का गठन भी किया गया है। वर्तमान में इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन' पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल की आपूर्ति के लिए गांवों में पाइपों के जाल बिछ चुके हैं। हजारों की तादाद में सरकारी व निजी हैंडपंप लगाए जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है।

स्मरण रहे कि हमारे पुरखे जल आपूर्ति के लिए जल विभाग या जल मंत्रालयों पर निर्भर नहीं थे। पूर्वजों द्वारा पेयजल संग्रहण की सदियों पुरानी उत्तम पद्धति बावडियां व खातरियां आदि हिमाचल के गांवों में आज भी मौजूद हैं। इन पारंपरिक जलस्रोतों के गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल का आज भी कोई विकल्प नहीं है। कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जल प्रबंधन की पुरातन प्रणाली हिमाचल में 'कूहल' के नाम से विख्यात रही है। बावडियां, कुएं व तालाब आदि जल संरचनाओं के जरिए हर गांव को जलतंत्र विकसित करके पूर्वजों ने अनूठी मिसाल कायम की थी। इंसानों के अलावा जीव-जंतु, पशु-पक्षी तथा जंगली जानवरों के पानी को तलाशते सूखे हलक भी इन्हीं जल संसाधनों पर तर होते थे। ग्रामीण संस्कृति से गहरा नाता रखने वाले पारंपरिक जलस्रोतों का कृषि अर्थतंत्र को मुन्नवर करने में भी मुख्य किरदार रहा है। कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी जलाशयों के तटों पर होता आया है। मगर विडंबना है कि हमारे समाज की जीवनशैली में अंग्रेजी तहजीब इस कदर मुश्तमिल हुई कि अपने पूर्वजों की बेशकीमती विरासत पारंपरिक जलस्रोतों को खैरात में मिला गुजरे जमाने का नजऱाना समझ कर नजरअंदाज कर दिया गया। विनाश को अंजाम देने वाले जबरन विकास की आंधी में मशीनीकरण के प्रहारों से भूमिगत प्राकृतिक जलधाराएं लुप्त हो रही हैं। नतीजतन बावडियां, चश्में व झरने आदि जल सरंचनाओं का अस्तित्व भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। खनन माफिया की बढ़ती दखलअंदाजी ने खड्डों व नालों का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ दिया है।

उद्योगों व आग उगल रही फैक्टरियों से उत्पन्न जहरनुमा प्रदूषण से नदियों, खड्डों व प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी दूषित हो चुका है। सैकड़ों सरकारी हैंडपंप व पेयजल परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। अतः पहाड़ों में बसे सैकड़ों गांवों की पेयजल आपूर्ति का जरिया पुनः प्राकृतिक जलस्रोत ही बनेंगे। इनका वजूद बचाने में समाज के साथ शासन व प्रशासन को संगीदगी दिखानी होगी। ज्ञात रहे पेयजल की शदीद गर्दिश कई देशों में लाखों आबादी के पलायन का कारण बनी है। लिहाजा अपनी बदहाली पर अश्क बहा रहे पारंपरिक जलस्रोतों की खामोशी भविष्य में बड़े जल संकट की आहट का इशारा करती है।

इनसाइड

लिस्टिंग से पहले उछला GMP, आनलाइन चेक करें अलाटमेंट स्टेटस

DCX IPO Allotment Status DCX Systems IPO का आज अलॉटमेंट किया जा रहा है। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी उछाल पर है। BSE वेबसाइट पर लॉग इन करके इसकी ऑनलाइन जांच की जा सकती है। अगर आपने अप्लाई किया है तो स्टेटस चेक कर लें।

नई दिल्ली। DCX Systems Limited के IPO शेयर आवंटन की घोषणा आज होने की संभावना है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक तीन दिनों की बोली के दौरान निवेशकों ने DCX Systems IPO के प्रति खासा उत्साह दिखाया है। ग्रे मार्केट में 500 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू पर तेजी पर बना हुआ है। डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ का जीएमपी 78 है। सुबह के सत्र में यह 75 के स्तर पर था।

DCX सिस्टम्स IPO GMP

बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, DCX सिस्टम्स IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) आज 78 है, जो कल के GMP 75 प्रति इक्विटी शेयर से 3 रुपये अधिक है। पिछले दो दिनों से DCX सिस्टम्स के शेयर की कीमत ग्रे मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

DCX सिस्टम्स IPO: आनलाइन जांच कैसे करें

जिन लोगों ने 500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन किया है, वे बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट bseindia.com या आईपीओ के आधिकारिक रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति की आनलाइन जांच कर सकते हैं।

DCX सिस्टम्स IPO के लिए नियुक्त आधिकारिक रजिस्ट्रार Link Intime Private Limited है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट linkintime.co.in है। शेयर आवंटन की घोषणा के बाद बोलीदाता इन वेबसाइटों पर अपने आईपीओ आवेदन की स्थिति की आनलाइन जांच कर सकते हैं।

ये है तरीका

बीएसई के लिंक bseindia.com/investors/appli_check.aspx या सीधे लिंक इनटाइम वेब लिंक linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html पर लॉगिन कर शेयरों की जांच की जा सकती है।

बीएसई लिंक पर लॉग इन करें- bseindia.com/investors/appli_check.aspx;

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ चुनें

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ आवेदन संख्या दर्ज करें

अपना पैन डिटेल दर्ज करें

'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

आपकी DCX सिस्टम्स IPO आवंटन स्थिति कंप्यूटर मॉनीटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी

डायरेक्ट इनटाइम लिंक

शेयर आवंटन की घोषणा के बाद, बोलीदाता सीधे लिंक इनटाइम वेब लिंक linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html पर लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका यह है।

डायरेक्ट लिंक इनटाइम वेब लिंक पर लॉग इन करें- linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html;

डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ चुनें

अपना पैन नंबर दर्ज करें

'सर्च' विकल्प पर क्लिक करें

आपकी DCX सिस्टम्स IPO आवंटन स्थिति कंप्यूटर मॉनीटर या स्मार्टफोन स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को दूसरी तिमाही में 2,749 करोड़ का घाटा

एनटीवी न्यूज

- तीनों कंपनियों को विपणन मार्जिन में गिरावट की वजह से हुआ नुकसान

- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में संयुक्त घाटा 21,201.18 करोड़ रुपये रहा

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को लगातार दूसरी तिमाही में घाटा हुआ है। इन तीनों कंपनियों को वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कुल 2,748.66 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इन तीनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह नुकसान पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर विपणन मार्जिन में गिरावट की वजह से हुआ है। हालांकि, सरकार ने एलपीजी के लिए इन कंपनियों को एकमुश्त 22,000 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान से नुकसान कम हुआ, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सका है।

आईओसी को 30 सितंबर को समाप्त जुलाई-सितंबर तिमाही में 272.35 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पहली तिमाही में 1,995.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। एचपीसीएल को दूसरी तिमाही में 2,172.14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि पहली तिमाही में 10,196.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसी तरह बीपीसीएल का घाटा जुलाई-सितंबर तिमाही में 304.17 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहली तिमाही में 6,263.05 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एक अप्रैल से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इन तीनों कंपनियों का संयुक्त घाटा 21,201.18 करोड़ रुपये रहा।

आईपीओ निवेश में इन गलतियों से बचें

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। भारत में आईपीओ बाज़ार पिछले कुछ वर्षों से फलफूल रहा है, खासकर कोरोना महामारी के बाद ये अधिक परिपक्व हुआ है। बड़ी संख्या में रिटेल निवेशकों के प्रवेश और शेयर बाज़ार में निरंतर बढ़ती रैली ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है। चाहे आप किसी कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हों या केवल तुरंत लाभ कमाना चाहते हों, आईपीओ निवेश कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए'

आईपीओ में निवेश करते समय इन गलतियों से बचना चाहिए:

कारोबार के विषय में नहीं जाननाः निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि भले ही वे सिर्फ एक आईपीओ में पैसा लगा रहे हों, लेकिन निवेश की मूल बातें वही रहती हैं. यह जानना कि वे कहां निवेश कर रहे हैं, यह सर्वोपरि है। आईपीओ में निवेश किसी व्यवसाय में स्टॉक खरीदने के समान है जिसे आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं। आईपीओ निवेश के निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले, वेबसाइट, व्यापार पत्रिकाओं, पुराने कर्मचारियों, मैनेजमेंट इंटरव्यू आदि जैसे स्रोतों से अधिक से अधिक जानकारी इक_ा करने का प्रयास करें। ग्राहकों और कंपनी की वित्तीय स्थिति, देनदारियों, ऋण स्थिति और भविष्य की विकास संभावनाओं को समझने की कोशिश करें। किसी व्यवसाय का सार उसकी लाभ कमाने की क्षमता पर आधारित होता है। इसलिए आपको इसकी लाभ कमाने की क्षमता का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए।

शोध नहीं करना: ब्रोकर, डीमैट सेवा प्रदाता या सलाहकार जो आपको बताते हैं, उस पर पूरी तरह से न जाएं। सबसे पहले आईपीओ के कारण की जांच करें और कंपनी आईपीओ आय का उपयोग कैसे करेगी, यह जानने का प्रयास करें। पिछले प्रदर्शन, आय प्रवाह, जोखिम, प्रकटीकरण आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मापदंडों की जांच भी करें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस डिजिटल युग में, कंपनी या प्रबंधन द्वारा किया गया हर कदम ऑनलाइन रजिस्टर होता है। इसलिए हर प्रकार की जानकारी कहीं न कहीं से उपलब्ध हो जाती है।

मूल्यांकन नहीं करना: निवेशकों को कंपनी के नकदी प्रवाह, वित्तीय अनुपात, लाभप्रदता, ऋण और एक ही व्यवसाय श्रेणी में प्रतिस्पर्धियों के प्रदर्शन को बारीकी से देखना चाहिए। हालांकि प्रतिस्पर्धा के साथ वैल्यूएशन मेट्रिक्स की तुलना करना हमेशा समझ में नहीं आता है, खासकर अगर यह तकनीक आधारित कंपनी या पूरी तरह से नया बिजनेस सेगमेंट है। कई मामलों में किसी कंपनी को दिया गया मूल्यांकन अनुचित प्रतीत होता है। निवेश बैंकरों के एक निश्चित मूल्य निर्धारित करने के अपने तरीके और कारण होते हैं। अगर किसी इश्यू की कीमत उचित नहीं है, तो वह डिस्काउंट पर खुलेगा। लिस्टिंग मूल्य तक पहुंचने में भी काफी समय लग सकता है। यह आपके हित में होगा कि आप जिस व्यवसाय से जुडने की योजना बना रहे हैं, उसके मूल्य का सही आकलन करें।

बुल मार्केट में प्रचार: तेज़ी के बाजार में आईपीओ को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की अधिक संभावना होती है, इसलिए प्रीमियम पर सूचीबद्ध होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह गिरावट वाले बाजार में लिस्टिंग लाभ और भागीदारी दोनों की संभावना कम हो जाती है। आईपीओ का प्लेसमेंट और समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ प्रमोटर अपने आईपीओ को बुल मार्केट में धकेल कर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए निवेशकों को ऐसी कंपनियों पर ध्यान देने की जरूरत है। लंबी अवधि की दृष्टि वाली अच्छी कंपनियों की पहचान और स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यापार मॉडल निश्चित रूप से सही व्यवसाय चुनने में मदद करेगा।

टॉप स्पीड 115 KM प्रतिघंटा; सिंगल चार्ज में 181 KM रेंज, बेमिसाल है OLA का यह स्कूटर

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस वक्त नंबर वन कंपनी ओला का एस-वन प्रो स्कूटर आपके लिए बेहत किफायती हो सकता है। OLA S1-Pro के तीन नए वैरिएंट्स बेहद खास हैं, जो आपको बेहतरीन माइलेज के अलाव लाजवाब फीचर्स देते हैं। बात अगर ओला एस-वन प्रो की करें तो इसमें 4 केडब्ल्यूएच क्षमता वाली लीथियम ऑयन बैटरी है, जो कि साढ़े छह घंटे में फुल चार्ज हो जाती है।

खास बात यह है कि यह बैटरी 18 मिनट की चार्जिंग पर 70 से 75 किलोमीटर चलने लायक हो जाती है। फुल चार्ज होने पर यह 170 किलोमटीर चलती है, लेकिन कंपनी का दावा 181 किलोमीटर का है। ओला एस-वन प्रो की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटी, जीपीएस, साइड स्टैंड डाउन, एंटीं थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, 36 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, सात इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सहित, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, गेट होम मोड, टेक मी होम लाइट्स से फीचर्स शामिल हैं।

व्हाट्सऐप ने मैसेज डिलीट करने का किया पक्का इंतजाम

व्हॉट्सऐप दुनिया के सबसे बड़े इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। मीटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने सोमवार को एक नया फीचर 'व्हाट्सऐप एक्सीडेंटल डिलीट' जारी किया है. अक्सर ऐसा होता है जब यूजर्स 'डिलीट फॉर एवरीवन' करने के बजाय 'डिलीट फॉर मी' पर क्लिक कर देते हैं. ऐसे में यूजर्स को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, वॉट्सऐप द्वारा जारी लेटेस्ट फीचर यूजर्स को 'डिलीट फॉर एवरीवन' पर क्लिक करने का एक और मौका देगा। व्हाट्सऐप का एक्सीडेंटल डिलीट फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को और भी ज्यादा मजबूत करता है। यूजर्स जब भी मैसेज डिलीट करते हैं, तो 'डिलीट फोर एवरीवन' और 'डिलीट फॉर मी' ऑप्शन आता है। 'डिलीट फोर एवरीवन' से सभी के लिए मैसेज डिलीट हो जाता है। वहीं, अगर यूजर 'डिलीट फॉर मी' ऑप्शन पर क्लिक करता है तो केवल उस यूजर के लिए ही वो मैसेज डिलीट होता है, बाकि कांटैक्ट उस मैसेज को देख सकते हैं। हालांकि, अब वॉट्सऐप ने यूजर्स को गलती सुधारने का एक मौका दिया है। अगर कोई मैसेज डिलीट करने के लिए यूजर 'डिलीट फोर एवरीवन' की जगह 'डिलीट फोर मी' ऑप्शन पर क्लिक करता है तो मैसेज डिलीट होने के बाद भी दूसरे यूजर्स उस मैसेज को देख सकते हैं। वहीं, नए फीचर के साथ अगर आप गलती से 'डिलीट फॉर मी' पर क्लिक करते हैं तो एक पॉप नजर आता है, जो आपको डिलीट अनडू करने का मौका देता है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को गलती सुधारने के लिए पांच सेकेंड मिलेंगे। व्हॉट्सऐप का नया फीचर गलती से 'डिलीट फॉर मी' किए मैसेज को अनडू करने का मौका देता है।

बिजली संयत्रों के पास कोयले का भंडार 2.56 करोड़ टन हुआ

नईदिल्ली, । कोयले की कमी से बिजली संकट का सामना दोबारा न हो, इसके लिए इसकी आपूर्ति बढ़ा दी गई है। देश में ताप बिजली संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 31 अक्टूबर तक बढ़कर 2.56 करोड़ टन हो गया है। बिजली क्षेत्र को घरेलू कोयले की आपूर्ति पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12 फीसदी अधिक है।

कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि देश में ताप बिजली संयंत्रों के पास 31 अक्टूबर तक कोयले का भंडारण 12 फीसदी बढ़कर 2.56 करोड़ टन हो गया है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वर्ष 2020-21 को छोड़कर यह अक्टूबर महीने में अब तक का यह सर्वाधिक कोयला भंडार है। इसके साथ ही यह किसी भी वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में बिजली क्षेत्र को होने वाली सर्वाधिक कोयला की आपूर्ति है।

मंत्रालय के मुताबिक कोयले का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए 141 नई कोयला खानों को हाल में नीलामी के लिए रखा गया है। कोयला मंत्रालय इससे पहले नीलाम की गई कोयला खदानों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर समन्वय कर रहा है। कोयला मंत्रालय पीएम-गतिशक्ति के तहत सभी प्रमुख खानों के लिए रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि कोयला तेजी से निकाला जा सके।

उल्लेखनीय है कि इस साल गर्मी के मौसम में कोयले की कमी के कारण कई राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने कहा था कि बिजली संकट मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में तेज गिरावट के कारण हुआ, न कि घरेलू कोयले की अनुपलब्धता के कारण। इसके बाद से कोयला मंत्रालय बिजली क्षेत्र को कोयले की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

सुजुकी मोटर को दूसरी तिमाही में पांच हजार करोड़ रुपये का मुनाफा

नई दिल्ली। जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। कंपनी का दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में परिचालन मुनाफा एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में दोगुना होकर करीब पांच हजार करोड़ रुपये रहा है।

सुजुकी मोटर ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में उसका परिचालन लाभ 89.8 अरब येन (करीब 5,000 करोड़ रुपये) हो गया। कंपनी ने परिचालन लाभ में इस तीव्र बढ़ोतरी के लिए भारत समेत तमाम बाजारों में बिक्री बढ़ने को श्रेय दिया है।

कंपनी के मुताबिक इस दौरान उसकी शुद्ध बिक्री 39.3 फीसदी बढ़कर 1,154.1 अरब येन (करीब 64,000 करोड़ रुपये) हो गई जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 828.2 अरब येन रही थी। सुजुकी मोटर ने कहा कि अप्रैल-सितंबर की छमाही में उसकी कुल वाहन बिक्री 14.63 लाख इकाई पर पहुंच गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसने 12.55 लाख वाहन बेचे थे। उल्लेखनीय है कि जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी भारत में मारुति के साथ मिलकर मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के जरिए परिचालन करती है।

एक साल के उच्चतम स्तर पर सरकारी बैंकों के शेयर, जानिए किसमें मिल रहा सबसे अच्छा मुनाफा

नई दिल्ली, । सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों ने 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर को छूकर बेंचमार्क से भी बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तिमाही में अपनी कमाई से सुर्खियों में आए सरकारी बैंकों के शेयरों में हाल के दिनों में अच्छा उछाल देखने को मिला है। कल दलाल स्ट्रीट पर ये 5 शेयर 4-10% की तेजी के साथ बंद हुए।

सोमवार को लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी 50 के साथ क्रमशः 61,100 और 18,200 अंक को पार किया। बैंकिंग शेयरों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बेहतर प्रदर्शन के साथ रैली का नेतृत्व किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ये पांच बैंक हैं- इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया।

इंडियन बैंक के शेयर सोमवार को BSE पर 4.17% बढ़कर 259.85 रुपये पर बंद हुए। दिन में स्टॉक ने 269 रुपये के नए 52 सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ। इसका मार्केट कैप करीब 32,362.79 करोड़ रुपये है। एक साल में दलाल स्ट्रीट पर इंडियन बैंक के शेयर 47 फीसद से अधिक चढ़े हैं।

दूसरी तिमाही के दौरान इंडियन बैंक के शुद्ध लाभ में सालाना 12% की वृद्धि के साथ 1,225 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। शुद्ध ब्याज आय (NII) साल-दर-साल 15% बढ़कर 4,684 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सकल एनपीए 226 आधार अंकों की गिरावट के साथ 7.39% और शुद्ध एनपीए 176 आधार अंकों की गिरावट के साथ 1.5% वर्ष-दर-वर्ष हो गया।

बीओबी बीएसई पर 9.55% की वृद्धि के साथ 158.35 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को शेयरों ने 161.75 के नए स्तर को छुआ था। इसका मार्केट कैप करीब 81,888.52 करोड़ है। एक साल में डी-स्ट्रीट पर BoB के शेयरों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

FY23 की दूसरी तिमाही में, बैंक ने सालाना 58.70% की वृद्धि के साथ रुपये 3,312.42 करोड़ का एक स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया। बैंक का NII 34.47% yoy बढ़कर ₹10,174.46 करोड़ हो गया।

मुंबई स्थित पीएसबी 6.07% बढ़कर बीएसई पर 58.55 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक ने सोमवार को 59.10 रुपये के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ था। इसका मार्केट कैप लगभग 40,017.45 करोड़ रुपये है। एक साल में यूनियन बैंक के शेयरों में करीब 9 फीसदी का उछाल आया है।

यूनियन बैंक ने पिछले महीने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। Q2FY23 के दौरान, बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष 21.07% की वृद्धि के साथ 1,848 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि शुद्ध ब्याज आय (NII) वर्ष-दर-वर्ष 8,305 करोड़ रुपये रही।

सोमवार को केनरा बैंक के शेयर बीएसई पर 4.23% बढ़कर 309.45 रुपये पर बंद हुए। बैंक ने इससे पहले दिन में 52-सप्ताह के उच्च स्तर 311.80 को छुआ था। इसका मार्केट कैप करीब 56,138.26 करोड़ है। एक साल में शेयरों में करीब 27 फीसदी का उछाल आया है। सोमवार को सरकार ने टीसीएस के पूर्व उपाध्यक्ष विजय श्रीरंगन को बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।

जम्मू कश्मीर में खजाने का मिला ऐसा भंडार, जिससे बदल जाएगी देश की तकदीर, जानें सबकुछ

एनटीवी न्यूज

इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इससे देश को कितना फायदा मिलेगा? हमें और आपको इसका क्या लाभ मिलेगा? चीन इससे क्यों परेशान हो रहा है? आइए जानते हैं....

नई दिल्ली। भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है, जो पूरे देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये खजाना है 'लिथियम' का। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। इसकी क्षमता 59 लाख टन है। इसे 'व्हाइट गोल्ड' भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लीथियम मिला है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने से नॉन फेरस मेटल के क्षेत्र में अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इससे देश को कितना फायदा मिलेगा? हमें और आपको इसका क्या लाभ मिलेगा? चीन इससे क्यों परेशान हो रहा है? आइए जानते हैं....

पहले जान लीजिए पूरा मामला क्या है?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के विशेषज्ञ तीन साल से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली गांव में सर्वे कर रहे थे। इस दौरान यहां छह हेक्टेयर जमीन में सबसे हल्के खनिज लीथियम का 59 लाख टन भंडार पाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लीथियम खनिज भंडार का घनत्व भी बहुत अधिक है। यानी जिस क्षेत्र में यह खनिज पाया गया है, उसमें लीथियम को ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकेगा।

लीथियम की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे सलाल गांव के पहाड़ों में कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हो भी सकते हैं। कश्मीर में खनन सचिव अमित शर्मा ने बताया कि सामान्यतः लिथियम 220 पाट्र्स पर मिलियन (पीपीएम) ग्रेड पर मिलता है, लेकिन माता वैष्णो देवी तीर्थ की पहाड़ियों के नीचे मिला लीथियम 500 पीपीएम से ज्यादा ग्रेड का है।

आखिर ये लिथीयम है क्या?

लिथियम एक तरह का रेअर एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल मोबाइल-लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) समेत दूसरे चार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम (Li) एक नरम और चाँदी जैसी-सफेद धातु होता है। लिथियम का प्रयोग कई उत्पादों में किया जाता है और इसका भंडार मिलना भारत के लिए बड़ी क्रांति साबित हो सकती है।

लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल एल्युमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने के साथ ही मिश्र धातुओं की क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल कवच बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्युमीनियम-लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल साइकिलों के फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई-स्पीड ट्रेनों में भी किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है।

अब आगे क्या?

इसे समझने के लिए हमने कश्मीर में खनन सचिव अमित शर्मा से बात की। उन्होंने कहा, 'जीएसआई ने लीथियम की तलाश के लिए जी-3 स्तर के अध्ययन करवाए हैं। अब जी-2 और जी-1 स्तर के सर्वे होंगे। लीथियम उत्खनन में कितना समय लगेगा, यह इन सर्वे पर ही निर्भर करता है। विभाग की कोशिश है कि जल्द उत्खनन के लिए बचे हुए काम समय से पूरे हों।'

लिथियम का भंडार मिलने से क्या होगा?

फिलहाल भारत 96 प्रतिशत लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और बोलीविया से करता है। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के निर्यात से भारत की काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लिथियम भंडार भारत में मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होने से तो बचेगी ही। साथ ही भारत लिथियम का निर्यात कर अपना राजस्व भी बढ़ा सकेगा।

लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 93 लाख टन का है। ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन, अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में 20 लाख टन लिथियम उत्पाद किया जाता है। भारत चीन से सबसे ज्यादा लिथियम आयात करता है। जो पूरे आयात का 80 प्रतिशत है। साल 2020-21 के बीच भारत ने लिथियम ऑयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं साल 2021-22 में लिथियम के आयात पर 13,838 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

मौजूदा समय में एक टन लिथियम की कीमत

करीब 57.36 लाख रुपये है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे में आज के समय इसकी कीमत लगभग 3,384 अरब रुपये होगी। बता दें कि कमोडिटी मार्केट हर दिन मेटल की कीमत तय करता है।

लिथियम का भंडार मिलने से देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एनर्जी, बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे देश में ही रोजगार सृजन होगा।

भारत ने साल 2070 तक अपने उत्सर्जन को पूरी तरह से इनवायरमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी में लिथियम का एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप होना जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक 27 GW ग्रिड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होगी, जिसके लिये भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में लिथियम का भंडार मिलना पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी है।

कुछ और सवालों के जवाब भी जान लीजिए...

1. क्या लिथियम भंडार मिलने से बैटरियों की कीमत पर असर पड़ेगा?

एनर्जी सेक्टर की जानकारी रखने वाले प्रो. मनोज शुक्ला कहते हैं, 'अगर भारत अपने भंडार से जरूरत के मुताबिक लिथियम का उत्पादन कर लेता है तो जाहिर है कि बैटरियों के दाम कम होंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में भी कमी आ सकती है।'

2. जलवायु परिवर्तन पर कितना असर होगा?

प्रो. शुक्ला के अनुसार, 'जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ही पूरी दुनिया में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी इसपर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया को लिथियम बैटरियों से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर भारत जरूरत के जितना लिथियम उत्पाद कर लेता है और दूसरे देशों में निर्यात करने लगे तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को काबू किया जा सकता है।'

इनसाइड

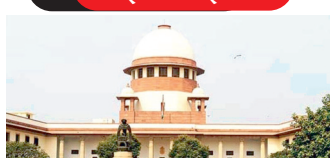

आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को न बनाएं हथियार, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल आरोपियों को परेशान करने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे-मोटे (तुच्छ) मामले कानून की पवित्र प्रकृति को विकृत न करें। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एसआर भट्ट की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले साल अगस्त के फैसले के खिलाफ एक अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून निर्दोषों की रक्षा के लिए ढाल की तरह है। उन्हें डराने के लिए तलवार के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले साल अगस्त के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की।

दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधान के कथित उल्लंघन के संबंध में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।

महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पार कर रही महिलाओं को एसयूवी ने मारी टक्कर, पांच की मौत

एनटीवी संवाददाता

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात 10.45 बजे शिरोली गांव के करीब हुई। यहां 17 महिलाएं हाईवे पार करने की कोशिश कर रही थीं। ये सभी 50 किमी दूर पुणे शहर से आई थीं।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां नासिक-पुणे हाईवे पर एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे महिलाओं के समूह को कुचल दिया। इस घटना में पांच महिलाओं की मौत हुई है, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात 10.45 बजे शिरोली गांव के करीब हुई। यहां 17 महिलाएं हाईवे पार करने की कोशिश कर रही थीं। ये सभी 50 किमी दूर पुणे शहर से आई थीं और हाईवे के दूसरी तरफ स्थित मैरिज हॉल में कैटरिंग के काम के लिए जा रही थीं। जब ये महिलाएं सड़क पार कर रही थीं, ठीक उसी वक्त पुणे की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी उनसे टकरा गई। इस घटना के बाद एसयूवी ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा ली और यू-टर्न लेकर वापस पुणे की ओर लौट गया। इस घटना में जहां दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा तीन अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में एसयूवी ड्राइवर के खिलाफ

केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

पालघर में सड़क दुर्घटना में तीन की मौत

इस बीच पालघर में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर भी एक दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर बाइक सवार तीन लोग एक ट्रैक्टर ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसा दहानू जालुका के पास मुंबई से कुछ 120 किमी दूर हुआ। बाइक सवार लोग पेट्रोल के लिए जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने फ्यूल स्टेशन के लिए गाड़ी मोड़ी, ट्रैक्टर ट्रेलर से उन्हें टक्कर मार दी औश्र वहां से भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई में वॉटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल, पानी के लिए जूझ रहे होटल-मॉल और हाउसिंग सोसाइटी

मुंबई। मुंबई में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के लिए टैंकर संचालकों के लिए लाइसेंस व राजस्व का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा निजी टैंकर मालिकों के पास भूमिगत जल निकालने के लिए 2,000 वर्ग फुट का भूमि पार्सल होना चाहिए। मुंबई में बीते पांच दिनों से जारी वॉटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल ने अब जल आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऐसोसिएशन की ओर से दावा किया गया है कि हड़ताल के कारण कई होटल, क्लब, मॉल व हाउसिंग सोसाइटी में जल संकट खड़ा हो गया है। बता दें, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नए दिशानिर्देशों के विरोध में ऐसोसिएशन के करीब 2500 टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसोसिएशन की मांग है कि वह बिना लिखित आश्वासन के अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। दरअसल, मुंबई में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के लिए टैंकर संचालकों के लिए लाइसेंस व राजस्व का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा निजी टैंकर मालिकों के पास भूमिगत जल निकालने के लिए 2,000 वर्ग फुट का भूमि पार्सल होना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि टैंकर मालिकों और आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा जमा के रूप में स्थानीय प्रशासन को 6,50,000 रुपये का भुगतान करना होगा और पांच से अधिक टैंकर एक विशिष्ट बिंदु से पानी नहीं खींच सकते हैं। प्राधिकरण के नए दिशानिर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र, बोले- राज्य बना विकास का प्रतीक

एनटीवी संवाददाता

नड्डा ने कहा, सत्ता की बागडोर किसे सौंपी जाए, यह मामूली आधारों पर तय नहीं किया जाता, इसके लिए बहुत ही गहन विचार-विमर्श की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि पांच साल पहले पिछली सरकारों में नगालैंड को बंद, नाकाबंदी, उग्रवाद, अपहरण और टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता था।

नगालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा पहुंचे। यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि पांच साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अवरोध, उग्रवाद, लक्षित हमले आदि का सामना करना पड़ता था। मगर आज नागालैंड फिर से शांति, समृद्धि और विकास की राह पर आ गया है। नागालैंड की विकास की एक कहानी रही है। पिछले आठ सालों में विद्रोह 80% कम हो गए हैं और AFSPA 66% क्षेत्रों से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों को 'अष्ट लक्ष्मी' मानते हैं, उनमें विकास के आधार पर शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी संकेत, संस्कृति, प्राकृतिक-खेती और खेल के साथ-साथ अन्य क्षमताएं हैं।

इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के नेता नेफ्यू रियो की उपस्थिति में एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने मंगलवार को कहा कि आज नगालैंड में शांति है, राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। नड्डा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में आज नगालैंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। नगालैंड के हर वर्ग की समस्या को हम सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजाती लोगों से बहुत प्यार है, वे चाहते हैं कि नगालैंड के लोग भी विकास में सहभागी बनें।

कोहिमा में आयोजित एक समारोह के संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, पहले की सरकारों की पहचान बंद, नाकेबंदी, अपहरण, टारगेट हत्या और आतंकवाद के लिए जानी जाती थीं। लेकिन जबसे नेफ्यू रियो ने नगालैंड की बागडोर संभाली है, प्रदेश का नक्शा ही बदल गया है। उनके नेतृत्व में आज नगालैंड शांति और समृद्धि का स्थल बन गया है। आज नगालैंड में विकास की बयार चल पड़ी है। हर ओर विकास आपको दिखाई देता है।

उन्होंने कहा, नगालैंड के लोग बहुत बड़े देशभक्त हैं। उनके अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। यहां की संस्कृति बहुत और यहां की प्रकृति देश और दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातियों के प्रति प्यार जग-जाहिर है। उनकी ही देन है कि आज देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलीं। आदिवासियों के प्रति उनका सम्मान ही है कि आज देश में तीन राज्यपाल जनजाति समुदाय से हैं और उनकी कैबिनेट में आठ मंत्री जनजाति समुदाय से हैं।

उन्होंने कहा, आज देश देने वाला बन गया है, लेना वाला रह नहीं गया है। हमने कोरोनाकाल में जो काम करके दिखाया, पूरी दुनिया चकित रह गई। आज अगर आप सभी यहां पर बिना मास्क के बैठे हैं, तो उसकी वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच। आज देश में सौ फीसदी वैक्सीनेशन हो चुका है। लोगों को डबल डोज मिल चुकी है। अब को बूस्टर भी मिलने लगी है। उन्होंने कहा, नगालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व में जो काम किया गया है, उसका लाभ गठबंधन को जरूर मिलेगा।